- 19th Year
- Issue: 242
- 08.01.2026 (THURSDAY)
- ROURKELA
- R.N.I. No. ORIHIN/2006/18978
- (Pages-6)
- Price:2.00

दैनिक

कलिंग समाचार

The kalingasamachar

e-paper-www.thekalingasamachar.com

प्रकाशक एवं संपादक : प्रकाश कुमार धल

Published From ODISHA, JHARKHAND & CHHATTISHGARH

उत्तर प्रदेश में एसआईआर के बाद मसौदा मतदाता सूची जारी, दो करोड़ 89लाख नाम कटे

लखनऊ ०७/०१ (संवाददाता): उज़र प्रदेश में लगभग हर पांचवें वोटर का नाम स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (स्ङ्क्र) के बाद हटाया जा सकता है, ज़्योंकि इलेज़्शन कमीशन ऑफ इंडिया (श्वष्टढ्ढ) ने मंगलवार को ड्राज़्ट रोल जारी किया, जिसमें 28.9 मिलियन लोगों के नाम हटा दिए गए हैं।

यह उन बड़े राज्यों में सबसे ज़्यादा प्रतिशत है जहां यह विवादित प्रक्रिया चलाई गई है।यह आंकड़ा पूर्व की संज़्या 15.44 करोड़ से लगभग दो करोड़ 89 लाख कम है। राज्य के मुज़्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) नवदीप रिणवा ने मंगलवार को एक संवाददाता सज़्मेलन में बताया कि एसआईआर की प्रक्रिया के बाद मसौदा मतदाता सूची जारी कर दी गयी है।

इसमें 12 करोड़ 55 लाख 56 हजार 25 मतदाता शामिल हैं। पिछले साल 27 अज़्टूबर की मतदाता सूची में 15 करोड़ 44 लाख 30 हजार 92 मतदाता थे। मसौदा सूची में लगभग 2.89 करोड़ मतदाताओं को गिनती के दौरान शामिल नहीं किया जा सका है। सीईओ ने कहा कि अब मसौदा मतदाता सूची पर दावे और आपज़ियां छह जनवरी से छह फरवरी तक दर्ज करायी जा सकेंगी। इस दौरान लोग सूची में नाम शामिल करने, सुधार करने या आपज़ि करने के लिए आवेदन कर सकते हैं।

रिणवा ने आंकड़े जारी करते हुए कहा कि 46.23 लाख मतदाता (2.99 प्रतिशत) मृत पाए गए, जबकि 2.57 करोड़ मतदाता (14.06 प्रतिशत) या तो स्थायी रूप से बाहर चले गये थे या प्रमाणन की प्रक्रिया के दौरान मौजूद नहीं थे। वहीं, 25.47 लाख अन्य मतदाताओं

का नाम एक से अधिक स्थानों पर पंजीकृत पाया गया। उन्होंने कहा, मसौदा मतदाता सूची में अब 12.55 करोड़ मतदाता हैं और इसमें राज्य के सभी 75 जिले और 403 विधानसभा क्षेत्र शामिल हैं।

रिणवा ने बताया कि इस काम में एक लाख 72 हजार 486 बूथ शामिल किये गये थे। इनमें बूथ स्तरीय अधिकारी (बीएलओ) फार्म भरवाने के लिये मतदाताओं तक पहुंचे थे।

उन्होंने बताया कि मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों द्वारा नियुक्त 5,76,611 बूथ स्तरीय एजेंटों ने भी इस काम में मदद की। सीईओ ने बताया कि प्रदेश में एसआईआर की कवायद मूल रूप से 11 दिसंबर को खत्म होने वाली थी लेकिन लगभग दो करोड़ 97 लाख मतदाताओं के नाम मसौदा सूची से बाहर हो रहे थे जिसके बाद 15 दिन का अतिरिक्त समय मांगा गया।

इसके मद्देनजर निर्वाचन आयोग की मंज़ूरी से एसआईआर प्रक्रिया की अवधि 26 दिसंबर तक बढ़ा दी गयी थी। रिणवा ने बताया कि शुरू में मसौदा मतदाता सूची जारी करने की तारीख 31 दिसंबर तय की गई थी लेकिन अपरिहार्य कारणों से बाद में इसे छह जनवरी कर दिया गया। उज़र प्रदेश में विपक्षी दलों ने मतदाता सूची के मसौदा तैयार करने के बाद उसकी आलोचना की है। उप्र कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने 'पीटीआई वीडियो' से बात करते हुए कहा कि मतदाता सूची तैयार करने के लिए आवंटित समय बहुत कम था। उन्होंने कहा, ''यह पूरी तरह से जल्दबाजी में लिया गया निर्णय है।

उज़र प्रदेश जैसे बड़े राज्य में केवल एक महीने का समय देकर एसआईआर प्रक्रिया शुरू करने का तरीका अनुचित है।'' राय ने कहा, ''उन्होंने (निर्वाचन आयोग ने) केरल जैसे छोटे राज्य को भी एक महीने का समय दिया। उज़र प्रदेश को कम से कम पांच से छह महीने का समय दिया जाना चाहिए था, जैसा कि 2002-03 में किया गया था... अगर ऐसा किया गया होता, तो बूथ स्तरीय अधिकारियों (बीएलओ) पर इतना दबाव नहीं होता और आत्महत्याओं को रोका जा सकता था।'' समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपनी पत्नी डिंपल यादव के लोकसभा क्षेत्र मैनपुरी में मतदाता सूची के मसौदे को लेकर निर्वाचन आयोग को चेतावनी दी।

कन्नौज के सांसद और उज़र प्रदेश के पूर्व मुज़्यमंत्री ने 'एज़्स' पर कहा, ''मतदाताओं के गुस्से के आंदोलन में बदलने से पहले, निर्वाचन आयोग को मैनपुरी में एसआईआर से हटाए गए वैध नामों का संज्ञान लेते हुए मतदाता सूची को सही करना चाहिए।'

' कांग्रेस नेता गुरदीप सिंह सप्पल ने उज़र प्रदेश में एसआईआर की मसौदा सूची जारी होने के बाद मंगलवार को दावा किया कि उनका और उनके परिवार के सदस्यों के नाम एसआईआर से गायब हैं, जबकि उनके पास सारे कागजात हैं तथा 2003 की मतदाता सूची में भी उनके नाम थे।

कांग्रेस कार्य समिति के स्थायी आमंत्रित सदस्य ने कहा कि उनका नाम सिर्फ इस आधार पर काट दिया गया कि उन्होंने अपना नाम साहिबाबाद विधानसभा क्षेत्र से नोएडा विधानसभा क्षेत्र में स्थानांतरित कराया था।

इस बीच आयोग ने छह जनवरी से छह फरवरी तक आपज़ि और दावे प्रस्तुत करने के लिए एक विंडो खोली है, जिसके दौरान कोई भी पात्र मतदाता जिसका नाम दर्ज नहीं है, फॉर्म-6 जमा करके अपना नाम दर्ज कराने के लिए आवेदन कर सकता है। एक से अधिक स्थानों पर पंजीकृत पाए गए मतदाताओं के नाम जांच के बाद केवल एक सत्यापित स्थान पर ही दर्ज रखे जाएंगे।

राष्ट्रपति मुर्मू का आदेश, अब केंद्र शासित प्रदेशों में प्रशासक लागू करेंगे औद्योगिक संबंध संहिता

नयी दिल्ली ०७/०१ (संवाददाता): राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सभी केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासकों और उपराज्यपालों को औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 के अंतर्गत उपयुक्त सरकार की शक्तियों का प्रयोग करने और कार्यों का निर्वहन करने के लिए अधिकृत किया है।

इस कदम का उद्देश्य सभी केंद्र शासित प्रदेशों में श्रम कानूनों के कार्यान्वयन में स्पष्टता और एकरूपता सुनिश्चित करना है।यह निर्देश संविधान के अनुच्छेद 239 के खंड (1) के तहत जारी किया गया है और 16 जनवरी, 2023 और 22 जून, 2023 को जारी की गई पिछली अधिसूचनाओं का स्थान लेता है।

हालांकि, गृह मंत्रालय द्वारा 2 जनवरी को जारी की गई नई अधिसूचना में यह स्पष्ट किया गया है कि पिछली अधिसूचनाओं के अंतर्गत पहले

से की गई या छोड़ी गई कार्रवाइयां अप्रभावित रहेंगी, जिससे निरंतरता और कानूनी निश्चितता बनी रहेगी। अधिसूचना के अनुसार, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव, चंडीगढ़, पुडुचेरी, लक्षद्वीप, लद्दाख और जज़्मू और कश्मीर के प्रशासक या उपराज्यपाल, राष्ट्रपति के नियंत्रण के अधीन रहते हुए और अगले आदेश तक, औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 के तहत उपयुक्त सरकार या राज्य सरकार की शक्तियों का प्रयोग करेंगे।

संविधान के अनुच्छेद 239 के खंड (1) के अनुसरण में और अधिसूचना संज़्या एस.ओ. 273(ई), दिनांक 16 जनवरी, 2023, एस.ओ. 2750(ई), दिनांक 22 जून, 2023 और एस.ओ. 2752(ई), दिनांक 22 जून, 2023 को निरस्त करते हुए, उन कार्यों को छोड़कर जो ऐसे निरस्तीकरण से पहले किए जाने थे या नहीं किए जाने थे, राष्ट्रपति एतद्वारा निर्देश देते हैं कि दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के प्रशासक या उपराज्यपाल।

गुरु तेग बहादुर के अपमान पर बवाल, आतिशी की सदस्यता रद्द करने की मांग

नयी दिल्ली ०७/०१ (संवाददाता): प्रवेश वर्मा और मंज़िंदर सिंह सिरसा समेत दिल्ली के कई मंत्रियों ने विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता को ज्ञापन सौंपकर गुरु तेग बहादुर के कथित अपमान के मामले में विपक्ष की नेता आतिशी की सदस्यता रद्द करने की मांग की। मीडिया से बात करते हुए प्रवेश वर्मा ने कहा, हमने विधानसभा अध्यक्ष को पत्र लिखकर आतिशी के कृत्य का संज्ञान लेते हुए उनकी सदस्यता रद्द करने की मांग की है... न केवल यह सदन बल्कि देश का हर नागरिक इससे आहत है। हमारे गुरुओं ने देश की अखंडता को मजबूत करने के लिए अपने प्राणों सहित पूरे परिवार के साथ बलिदान दिए, लेकिन विपक्ष की नेता, आम आदमी पार्टी की नेता ने उनका मजाक उड़ाया... हमें उज़्मीद है कि आतिशी की सदस्यता रद्द की जाएगी।दिल्ली विधानसभा में भाजपा विधायक द्वारा आतिशी की टिप्पणी पर तीखे विरोध प्रदर्शन को हवा देने के बाद भारी हंगामा हुआ। विधायकों ने मांग की कि विपक्ष की विधायक सत्र में उपस्थित हों और उनके खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाया जाए। कपिल मिश्रा ने कहा कि अध्यक्ष ने आतिशी के शज़्दों को पढ़ा... उन्होंने बेहद अपमानजनक भाषा का प्रयोग किया।

उन्होंने ऐसी अभद्र भाषा का प्रयोग तब किया जब विधानसभा गुरु तेग बहादुर जी के सज़्मान पर चर्चा कर रही थी। मैं उनके शज़्दों को दोहरा भी नहीं सकता। उन्हें विधानसभा में आना ही होगा, सिर्फ माफी मांगने से काम नहीं चलेगा।भाजपा विधायक हरीश खुराना ने कहा कि श्री गुरु तेग बहादुर की शहादत की 350वीं वर्षगांठ पर चर्चा चल रही थी।

2026 की शुरुआत इसरो पीएसएलवी-सी62 मिशन से करेगा, 12 जनवरी को श्रीहरिकोटा से लॉन्चिंग

नयी दिल्ली ०७/०१ (संवाददाता): इसरो नए साल के अपने पहले प्रक्षेपण की तैयारी में जुट गया है। पीएसएलवी-सी62 मिशन 12 जनवरी को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से उड़ान भरने वाला है। इसरो के एक अधिकारी के अनुसार, मिशन का मुज़्य पेलोड ईओएस-एन1 है, जो रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) द्वारा रणनीतिक उद्देश्यों के लिए विकसित एक इमेजिंग उपग्रह है। इसरो ने एज़्स पर पोस्ट में कहा कि पीएसएलवी-सी62 मिशन का प्रक्षेपण 12 जनवरी 2026 को भारतीय समयानुसार 10ः17 बजे एसडीएससी एसएचएआर, श्रीहरिकोटा के प्रथम प्रक्षेपण पैड (एफएलपी) से निर्धारित है। रॉकेट अपने साथ एक छोटा प्रायोगिक उपकरण, केस्ट्रेल इनिशियल डेमोंस्ट्रेटर (केआईडी) भी ले जाएगा। एक स्पेनिश स्टार्टअप द्वारा विकसित, केआईडी रॉकेट के पीएस-4 चरण से जुड़ा रहेगा। इसके अलावा, सूत्रों ने पुष्टि की है कि भारत, मॉरीशस, लज़्मबर्ग, यूएई, सिंगापुर, यूरोप और संयुक्त राज्य अमेरिका के स्टार्टअप और अनुसंधान

संस्थानों से 17 वाणिज्यिक पेलोड इस उड़ान के लिए भेजे जाने की पुष्टि की गई है। अंतरिक्ष प्रेमी एसडीएससी एसएचएआर, श्रीहरिकोटा स्थित लॉन्च व्यू गैलरी से लॉन्च का सीधा प्रसारण देख सकते हैं। पंजीकरण ऑनलाइन lvg.shar .gov.in पर उपलज़्ध है। इसरो आगंतुकों को सलाह देता है कि वे त्वरित और सुगम पंजीकरण प्रक्रिया के लिए सरकार द्वारा जारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस), मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी तैयार रखें। यह आगामी मिशन 2025 के बेहद सफल समापन के बाद आ रहा है। 24 दिसंबर को, इसरो ने एलवीएम3-एम6 मिशन का प्रक्षेपण किया, जिसके तहत ज़्लू बर्ड ज़्लॉक-2 उपग्रह को कक्षा में स्थापित किया गया। यह अंतरिक्ष यान एलवीएम3 रॉकेट द्वारा निज़न पृथ्वी कक्षा (एलईओ) में स्थापित किया गया अब तक का सबसे भारी पेलोड है। 223 वर्ग मीटर के विशाल फेज़्ड ऐरे एंटीना से सुसज्जित, यह एलईओ में स्थापित किया गया अब तक का सबसे बड़ा वाणिज्यिक संचार उपग्रह भी है। एलवीएम3 अपनी विश्वसनीयता को लगातार साबित कर रहा है, जिसने पहले चंद्रयान-2, चंद्रयान-3 और दो वनवेब नक्षत्रों जैसे महत्वपूर्ण मिशनों का प्रक्षेपण किया है। 24 दिसंबर की सफलता एलवीएम3-एम5/सीएमएस-03 मिशन के तुरंत बाद मिली, जो 2 नवंबर, 2025 को सफलतापूर्वक पूरा हुआ था।

अमित शाह तमिलनाडु में हिंदुओं की स्थिति को लेकर सरासर झूठ बोल रहे हैं-स्टालिन

०७/०१ (संवाददाता): तमिलनाडु के मुज़्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने बुधवार को कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का यह आरोप कि तमिलनाडु में हिंदुओं के अधिकार छीने जा रहे हैं, सरासर गलत है और उनके पद की गरिमा के अनुरूप नहीं है। मुज़्यमंत्री ने यहां एक सरकारी कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि उनकी सरकार सभी धर्मों के लोगों की आस्थाओं का सज़्मान करती है और उनके धार्मिक अधिकारों की रक्षा करती है। उन्होंने कहा, ''तमिलनाडु जैसे राज्य में गृह मंत्री का यह आरोप कि हिंदुओं के अधिकार छीने जा रहे हैं, सरासर गलत और उनके पद की गरिमा के अनुरूप नहीं है। सच तो यह है कि राज्य में दंगे और विभाजन पैदा करने की मंशा रखने वालों की मानसिकता सफल नहीं हुई है।'' स्टालिन ने कहा कि भविष्य में भी इस तरह की घटना कभी नहीं होगी और

''हम इसे होने नहीं देंगे।''

सज़ारूढ़ द्रविड़ मुनेत्र कषगम (द्रमुक) ने जोर देकर कहा, ''जब तक यह स्टालिन यहां है, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा।'' अमित शाह ने रविवार को तमिलनाडु के पुदुकोट्टई में एक जनसभा के दौरान द्रमुक पर राज्य में हिंदू धर्म और हिंदुओं की भावनाओं को लगातार अपमानित करने का आरोप लगाया था। केंद्र में सज़ारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के वरिष्ठ नेता ने हिंदुओं पर हुए 'अत्याचारों' को लेकर स्टालिन सरकार की कड़ी आलोचना की।उन्होंने आरोप लगाया कि हिंदू पूजा-पाठ के तरीकों का 'अपमान' किया जा रहा है और दावा किया कि अयोध्या राम मंदिर भूमि पूजा के दौरान राज्य में 'अघोषित कर्फ्यू लगा दिया गया था'। शाह ने कहा, ''उनके (द्रमुक के) वरिष्ठ नेता सनातन धर्म को डेंगू, मलेरिया कहते हैं। हिंदू शोभायात्राओं और विसर्जन (हिंदू देवी-देवताओं की मूर्तियों के विसर्जन) पर रोक लगा दी गई है। मैं स्टालिन से कहना चाहता हूं कि आपने हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार करके संवैधानिक मूल्यों का उल्लंघन किया है।

फर्जी खातों और टेरर फंडिंग के नेटवर्क पर जमू-कश्मीर पुलिस का कड़ा प्रहार! साइबर आतंकी मामले की जांच के तहत 22 जगहों पर रेड

श्रीनगर ०७/०१ (संवाददाता): जज़्मू-कश्मीर पुलिस ने बुधवार को साइबर आतंकी मामले की जांच के तहत घाटी में कई स्थानों पर छापेमारी की। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि जज़्मू-कश्मीर पुलिस की खुफिया रोधी शाखा (सीआईके) ने फर्जी खातों के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाई शुरू की है, पुलिस ने साइबर धोखाधड़ी और आतंकी विज़पोषण को बढ़ावा देने वाले ऐसे खातों पर शिकंजा कस दिया है। उन्होंने बताया कि साइबर आतंकी मामले की जांच के तहत सीआईके ने कश्मीर घाटी में 22 स्थानों पर छापेमारी की,

जिनमें श्रीनगर शहर के 15 स्थान शामिल हैं।

कोर्ट की मंजूरी मिलने के बाद किया गया यह ऑपरेशन कई ज़िलों, श्रीनगर, बडगाम, शोपियां और कुलगाम तक फैला हुआ था, जो सामान्य डिजिटल लेन-देन की आड़ में चल रहे एक गुप्त मनी-मूवमेंट नेटवर्क को खत्म करने के लिए पूरी घाटी में किए जा रहे प्रयास का संकेत देता है।

जांचकर्ताओं ने संदिग्ध फर्जी बैंक खातों के एक नेटवर्क को निशाना बनाया, जिनका इस्तेमाल कथित तौर पर साइबर फ्रॉड और ऑनलाइन घोटालों से मिले पैसे को ठिकाने लगाने और अवैध फंड को आतंकी नेटवर्क तक पहुंचाने के लिए किया जाता था।

छापों के दौरान, अधिकारियों ने मोबाइल फोन, लैपटॉप और स्टोरेज डिवाइस सहित डिजिटल डिवाइस, साथ ही विज़ीय दस्तावेज़ ज़्ज़त किए, जिनके बारे में माना जाता है कि उनमें नेटवर्क के संचालन से संबंधित महत्वपूर्ण सबूत हैं।

यह कार्रवाई ष्टढ्ढ्य के टेरर फाइनेंसिंग और भर्ती मॉड्यूल को खत्म करने के तेज़ प्रयासों का हिस्सा है। इससे पहले, 16 दिसंबर, 2025 को, ष्टढ्ढ्य ने सात ज़िलों, श्रीनगर, पुलवामा, बारामूला, कुलगाम, शोपियां, बडगाम और अनंतनाग में 12 जगहों पर छापे मारे थे, ताकि आतंकवाद के ऑनलाइन महिमामंडन पर केंद्रित एक आतंकी भर्ती मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया जा सके।

जांचकर्ताओं ने उन व्यक्तियों को भी निशाना बनाया है जिन पर राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए हानिकारक गतिविधियों को अंजाम देने के लिए मानवाधिकार वकालत प्लेटफॉर्म और सोशल मीडिया का दुरुपयोग करने का संदेह है।

यह नवीनतम ऑपरेशन हाइब्रिड खतरों पर ष्टढ्ढ्य के बढ़ते फोकस को दिखाता है जो साइबर अपराध को आतंकवाद के साथ मिलाते हैं, जो जज़्मू और कश्मीर में बढ़ते डिजिटल कट्टरपंथ के बीच एक बढ़ती चिंता का विषय है।

विविध समाचार

दिल्ली ने आधी रात को पत्थरबाजों को दिया संदेश-कानून का पहिया रुकेगा नहीं और पत्थरबाजी से अवैध कब्ज़ा बचेगा नहीं

नयी दिल्ली ०७/०१ (संवाददाता): अतिक्रमणकारियों को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से एक कड़ा और बड़ा संदेश गया है। हम आपको बता दें कि दिल्ली नगर निगम के 32 बुलडोजर धड़धड़ाते हुए अतिक्रमण वाले इलाके में पहुँचे और अवैध निर्माण को मिट्टी में मिला दिया। इस दौरान अतिक्रमणकारियों ने पथराव किया जिसके चलते पुलिस को सख़्ती करनी पड़ी। हम आपको बता दें कि दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश पर दिल्ली नगर निगम का दस्ता अतिक्रमण हटाने के लिए पहुँचा था लेकिन अतिक्रमणकारियों ने पथराव कर दिया जिसमें पांच पुलिसकर्मी घायल हो गए। स्थिति यह हो गयी कि हालात पर काबू पाने के लिए पुलिस को आंसू गैस का इस्तेमाल करना पड़ा। हालांकि बाद में स्थिति सामान्य कर दी गयी। बताया जा रहा है कि पुलिस ने अब तक 10 उपद्रवियों को गिरफ़्तार किया है।हम आपको बता दें कि पुलिस उपायुक्त (मध्य) निधिन वलसन ने कहा है कि एमसीडी को छह और सात जनवरी की दरमियानी रात को अतिक्रमण अभियान को अंजाम

देना था, जिसके मद्देनजर पुलिस कर्मियों को उन स्थानों पर तैनात किया गया था लेकिन एमसीडी का साजो सामान पहुंचने से पहले ही वहां लगभग 100-150 लोग इकट्ठा हो गए। अधिकारी ने बताया कि अदालत ने फैज़-ए-इलाही मस्जिद के पास स्थित एक 'बैंक्वेट हॉल' और एक औषधालय को अतिक्रमण घोषित किया था और इन्हें ही ढहाया जाना था। पुलिस ने बताया कि यह जमीन एमसीडी की है और उसने प्रस्तावित विध्वंस के बारे में पुलिस को पहले ही सूचित कर दिया था और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए बल की तैनाती की मांग की थी। उन्होंने कहा कि कार्रवाई से पहले स्थानीय लोगों को बताया गया कि यह कानूनी कदम है और इसके खिलाफ अपील का रास्ता खुला है। पुलिस के मुताबिक भीड़ के एक छोटे समूह ने उकसावे में आकर पथराव किया। जवाब में न्यूनतम बल का प्रयोग किया गया। घायलों को तत्काल चिकित्सा सहायता दी गयी। साथ ही दिल्ली पुलिस ने बताया है कि सीसीटीवी और ड्रोन फुटेज के आधार पर पहचान कर कानूनी कार्रवाई की जा रही है।

हम आपको यह भी बता दें कि एमसीडी के उपायुक्त विवेक कुमार ने कहा है कि यह विध्वंस अभियान उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में संचालित किया गया था, जिसके दौरान लगभग 36,000 वर्ग फुट अतिक्रमित क्षेत्र को खाली कराया गया। एमसीडी उपायुक्त विवेक कुमार ने बताया कि खाली कराए गए क्षेत्र में एक निदान केंद्र, एक विवाह हॉल और दो दोमंजिला चारदीवारी शामिल थीं। उन्होंने बताया कि ढहाने का काम पूरी रात जारी रहा। उन्होंने बताया कि घटनास्थल पर अब भी इतना मलबा पड़ा है जिससे लगभग 200 से 250 वाहन भरे जा सकते हैं और इसे सफाई अभियान के तहत हटाया जाएगा। विवेक कुमार ने स्पष्ट किया कि इस अभियान के दौरान मस्जिद को कोई क्षति नहीं पहुंची। उन्होंने कहा कि संरचनाओं को गिराने में समय लगा ज़्योंकि वे बेहद मजबूत थीं और उनकी दीवारें लगभग नौ इंच मोटी थीं।देखा जाये तो इस कार्रवाई से साफ है कि जो लोग अदालत के आदेश को चुनौती देने के लिए पत्थर उठाते हैं वे लोकतंत्र नहीं अराजकता की भाषा बोलते हैं। नगर निगम की यह कार्रवाई किसी समुदाय के खिलाफ नहीं बल्कि अवैध कब्ज़े के खिलाफ थी। जमीन सरकारी थी, आदेश न्यायालय का था और जिज़्मेदारी प्रशासन की थी। इसके बावजूद कुछ लोग भीड़ जुटाकर हिंसा पर उतर आए। यह सीधे सीधे कानून के शासन पर हमला है। सवाल साफ है। ज़्या सरकारी जमीन पर कब्ज़ा कर उसे आस्था की आड़ में बचाया जा सकता है। दिल्ली नगर निगम ने वही किया जो उसे करना चाहिए था।उसने किसी धार्मिक संरचना को हाथ नहीं लगाया बल्कि अवैध निर्माण हटाए। इसके बाद भी पुलिस पर पत्थर बरसाए गए। यह विरोध नहीं अपराध है। जो लोग घायल पुलिसकर्मियों पर चुप हैं वे बताएं कि ड्यूटी पर तैनात जवान की सुरक्षा का जिज़्मेदार कौन है। कानून व्यवस्था संभालने वाले हाथों पर पत्थर चलाना किसी भी सूरत में जायज नहीं ठहराया जा सकता। ऐसे तत्व समाज के दुश्मन हैं और इनके साथ सख़्ती ही एकमात्र इलाज है। देखा जाये तो दिल्ली नगर निगम और पुलिस ने संयम दिखाया। न्यूनतम बल प्रयोग किया। हालात संभाले और संदेश साफ दिया कि कानून से ऊपर कोई नहीं। अब वक्त है कि अतिक्रमणकारियों और पत्थरबाजों को यह समझा दिया जाए कि सरकारी जमीन कोई विरासत नहीं और अदालत का आदेश मजाक नहीं। अगर व्यवस्था को चुनौती दी जाएगी तो जवाब भी उसी दृढ़ता से मिलेगा। यह कार्रवाई सही थी, जरूरी थी और आगे भी जारी रहनी चाहिए। कानून का पहिया रुकेगा नहीं और पत्थरबाजी से अवैध कब्ज़ा बचेगा नहीं।

सरेंडर मोदी... राहुल गांधी ने अमेरिकी राष्ट्रपति के बयान को लेकर पीएम को घेरा

नयी दिल्ली ०७/०१ (संवाददाता): विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला बोला और उन पर दबाव में सरेंडर करने का आरोप लगाया। गांधी की यह टिप्पणी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस बयान के एक दिन बाद आई है, जिसमें उन्होंने हाउस व्हाइट मेंबर रिट्रीट में बोलते हुए दावा किया था कि पीएम मोदी ने उनसे मिलने का समय मांगा था। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा हाल के दिनों में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर की गई टिप्पणियों की पृष्ठभूमि में बुधवार को कटाक्ष करते हुए कहा कि ''फर्क समझो, सर जी।'' लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष ने पिछले साल जून में कांग्रेस के 'संगठन सृजन अभियान' से संबंधित एक कार्यक्रम में दिए गए अपने भाषण का एक अंश साझा किया, जिसमें उन्होंने दावा किया था कि प्रधानमंत्री मोदी, ट्रंप के एक फोन से उनके सामने झुक गए तथा ''नरेन्दर, सरेंडर'' कर गए। उस भाषण में राहुल गांधी ने यह भी कहा था कि कांग्रेस तथा उसके नेताओं ने महाशक्तियों के सामने कभी 'सरेंडर' नहीं किया, लेकिन थोड़े से दबाव के आगे झुक जाना ही भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मूल स्वभाव है। कांग्रेस नेता ने बुधवार को अपने इस भाषण से संबंधित वीडियो 'एज़्स' पर साझा करते हुए पोस्ट किया, ''फ़र्क समझो, सर जी।''दरअसल, ट्रंप ने भारत पर लगाए गए 50 प्रतिशत के टैरिफ (शुल्क) को लेकर हाल के दिनों में कई ऐसी टिप्पणियां की हैं जो सरकार को असहज करने वाली हैं। सरकार की तरफ से फिलहाल इन टिप्पणियों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने भी ट्रंप की टिप्पणियों को लेकर प्रधानमंत्री मोदी पर कटाक्ष किया।उन्होंने ट्रंप के वक्तव्य का वीडियो साझा करते हुए 'एज़्स' पर पोस्ट किया, ''नमस्ते ट्रंप से लेकर हाउडी मोदी तक, 'डोनाल्ड भाई' और अब यह (सर)। आगे ज़्या?'' अमेरिकी राष्ट्रपति ने मंगलवार को कहा कि रूसी तेल खरीदने पर अमेरिका द्वारा भारत पर लगाए गए शुल्क (टैरिफ) के कारण प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी उनसे 'ज्यादा खुश नहीं हैं।' ट्रंप ने 'हाउस जीओपी सदस्य रिट्रीट' में अपने संबोधन में यह भी दावा किया, ''प्रधानमंत्री मोदी मुझसे मिलने आए और बोले, ''श्रीमान, ज़्या मैं आपसे मिल सकता हूं?' मैने कहा, ''जी हां।

चंद्रबाबू नायडू ने अमित शाह से मुलाकात की, अमरावती के लिए वैधानिक दर्जे की मांग की

नयी दिल्ली ०७/०१ (संवाददाता): आंध्र प्रदेश के मुज़्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने बुधवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और अनुरोध किया कि संसद में एक विधेयक लाकर राज्य की राजधानी के रूप में अमरावती को वैधानिक दर्जा प्रदान किया जाए।नायडू ने कहा कि इस तरह का कदम राज्य के दीर्घकालिक विकास तथा स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण है। एक आधिकारिक बयान में कहा गया कि यहां शाह के आवास पर हुई बैठक में नायडू ने हाल में लागू विकसित भारत-जी राम जी योजना के विज़ीय प्रावधानों को लेकर चिंता भी जताई।उन्होंने कहा कि 60:40 के अनुपात में केंद्र और राज्य का परिवर्तित विज़पोषण आंध्र प्रदेश पर अतिरिक्त बोझ डालेगा और योजना के क्रियान्वयन को प्रतिकूल तरीके से प्रभावित कर सकता है। मुज़्यमंत्री ने राज्य की मौजूदा विज़ीय हालत को ध्यान में रखकर वैकल्पिक विज़ीय समर्थन देने का अनुरोध भी किया।

रूसी तेल पर बढ़ा विवाद, डोनाल्ड ट्रंप बोले- हमारे कड़े टैरिफ से पीएम मोदी खुश नहीं हैं

नयी दिल्ली ०७/०१ (संवाददाता): वॉशिंगटन में एक राजनीतिक कार्यक्रम के दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत और अमेरिका के बीच मौजूदा व्यापार तनावों को लेकर एक बार फिर बयान दिया है। बातों-बातों में ट्रंप ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनसे 'ज़्यादा खुश नहीं हैं', जिसकी वजह भारत पर लगाए गए भारी अमेरिकी टैरिफ हैं।

बता दें कि हाउस रिपब्लिकन पार्टी के मेंबर रिट्रीट को संबोधित करते हुए ट्रंप ने दावा किया कि प्रधानमंत्री मोदी उनसे मिलने आए थे और दोनों के रिश्ते अच्छे हैं, लेकिन मौजूदा हालात में असहजता है। ट्रंप के मुताबिक, भारत अब अमेरिका द्वारा लगाए गए ऊंचे टैरिफ चुका रहा है ज़्योंकि वह रूस से तेल खरीदने के मुद्दे पर वॉशिंगटन की अपेक्षाओं के मुताबिक पूरी तरह आगे नहीं बढ़ पाया है।

गौरतलब है कि ट्रंप प्रशासन ने भारतीय सामानों पर कुल 50 प्रतिशत तक टैरिफ लगाया है, जिसमें से 25 प्रतिशत शुल्क विशेष रूप से रूस से तेल आयात से जोड़ा गया है। मौजूद जानकारी के अनुसार, अमेरिका का आरोप है कि भारत सस्ता रूसी कच्चा तेल खरीदकर अप्रत्यक्ष रूप से रूस की आर्थिक मदद कर रहा है, जिसे ट्रंप ने बार-बार सार्वजनिक मंचों पर उठाया है।

अपने भाषण में ट्रंप ने यह भी कहा कि भारत ने हाल के महीनों में रूस से तेल आयात में कुछ हद तक कटौती की है और अमेरिका के साथ रक्षा सौदों पर आगे बढ़ रहा है। उन्होंने 68 अपाचे हेलीकॉप्टरों के ऑर्डर का ज़िक्र करते हुए कहा कि दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग जारी है और इसमें बदलाव की प्रक्रिया चल रही है। ट्रंप ने टैरिफ नीति का बचाव करते हुए यह दावा भी किया कि इन फैसलों से अमेरिका को आर्थिक रूप से फायदा हो रहा है। उनके अनुसार, सख़्त शुल्क नीति के ज़रिये अमेरिका अपने व्यापारिक हितों की रक्षा कर रहा है और साझेदार देशों को अपने रुख पर पुनर्विचार के लिए मजबूर कर रहा है।

हालांकि, भारत पहले ही ट्रंप के उस दावे को खारिज कर चुका है, जिसमें कहा गया था कि प्रधानमंत्री मोदी ने उनसे रूस से तेल खरीद बंद करने का आश्वासन दिया था। नई दिल्ली ने स्पष्ट किया था कि इस तरह की कोई बातचीत नहीं हुई है और भारत अपने राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए ऊर्जा नीति तय करता है।

गौरतलब है कि इसी बीच ट्रंप खुद को रूस-यूक्रेन युद्ध में संभावित मध्यस्थ के रूप में भी पेश कर रहे हैं। उन्होंने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की से बातचीत का ज़िक्र किया है, हालांकि अब तक किसी ठोस समाधान की घोषणा नहीं हुई है। ऐसे में भारत-अमेरिका व्यापार संबंध, रूस से तेल आयात और वैश्विक कूटनीति आने वाले समय में भी चर्चा का केंद्र बने रहने की संभावना है।

सिद्धरमैया के नाम जुड़ा शर्मनाक रिकॉर्ड! कर्नाटक बीजेपी ने घेरा, सिद्धारमैया को बताया सबसे बड़ा कर्जदार सीएम

नयी दिल्ली ०७/०१ (संवाददाता): कर्नाटक में विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने बुधवार को सिद्धरमैया को 'सबसे अधिक कर्ज लेने वाला मुज़्यमंत्री' करार दिया और उन खबरों का हवाला दिया जिनमें कहा गया है कि राज्य सरकार जनवरी से मार्च तक की चौथी तिमाही में 93,000 करोड़ रुपये का कर्ज ले सकती है। सिद्धरमैया द्वारा कर्नाटक के सबसे लंबे समय तक मुज़्यमंत्री रहने का इतिहास रचे जाने पर विपक्ष ने कर्ज को लेकर उनकी आलोचना की। सिद्धरमैया विज़ मंत्रालय का प्रभार भी संभाल रहे हैं।

विधानसभा में विपक्ष के नेता आर. अशोक ने कांग्रेस सरकार पर 'कर्नाटक को पीछे धकेलने' का आरोप लगाते हुए कहा कि सिद्धरमैया को यह समझना चाहिए कि इतिहास केवल कार्यकाल की अवधि को महत्व नहीं देता बल्कि उनके द्वारा छोड़ी गई विरासत के आधार पर उनका मूल्यांकन करता है।

उन्होंने कहा, सिद्धरमैया सिर्फ सबसे लंबे समय तक मुज़्यमंत्री रहने वाले नहीं बल्कि सबसे अधिक कर्ज लेने वाले मुज़्यमंत्री भी हैं। अशोक ने 'एज़्स' एक पोस्ट में कहा, आंकड़ों और विरा सत में अंतर यह है कि सबसे लंबे समय तक मुज़्यमंत्री रहने का खिताब महज एक आंकड़ा है। सबसे अधिक कर्ज लेने वाले मुज़्यमंत्री का खिताब एक विरासत है। उन्होंने कहा, इनमें से एक को भुला दिया जाएगा जबकि दूसरे को कर्नाटक के इतिहास में हमेशा के लिए याद रखा जायेगा। अशोक ने नवीनतम आंकड़ों को चौंकाने वाला बताते हुए कहा, एक ही तिमाही में 93,000 करोड़ रुपये का कर्ज, भारत में चौथी तिमाही में लिया जाने वाला अब तक का सबसे बड़ा कर्ज होगा। इसे शासन नहीं कहा जा सकता, यह घबराहट में किए गए विज़ीय प्रबंधन की सटीक परिहै।भाजपा नेता के अनुसार, यह कर्ज में भारी वृद्धि राजकोषीय ढांचे के पतन के कारण हुई है, जिनमें पिछले ऋणों को चुकाने के लिए उधार लेना, अस्थिर गारंटी योजनाओं को खतरनाक रूप से विज़पोषित करने के लिए उधार लेना और बुनियादी आर्थिक नियोजन की विफलता के कारण नकदी प्रवाह में भारी गिरावट आना शामिल है। उन्होंने कहा, 'जब किसी सरकार को केवल अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए हर महीने औसतन 31,000 करोड़ रुपये उधार लेने के लिए मजबूर होना पड़ता है, तो यह मजबूती का संकेत नहीं बल्कि राजकोषीय तनाव का स्पष्ट सूचक है।विपक्षी नेता ने कहा कि मुज़्यमंत्री सिद्धरमैया को यह समझना चाहिए कि इतिहास उनके खोखले कार्यकाल को महत्व नहीं देता। उन्होंने कहा, इतिहास उनके द्वारा छोड़ी गई विरासत के रिकॉर्ड का मूल्यांकन करेगा। और आज जो पीछे छूट रहा है वह निर्विवाद है- कर्ज का पहाड़, अक्षमता के स्पष्ट निशान और कर्नाटक राज्य का गिरवी रखा हुआ भविष्य।

'मोदी-शाह तेरी कब्र खुदेगी'..., जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में उमर खालिद और शरजील इमाम के समर्थन में नारेबाजी

नई दिल्ली ०७/०१ (संवाददाता): जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (छूह) एक बार फिर विवादों में घिर गया है। विश्वविद्यालय परिसर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह के खिलाफ आपज़िजनक नारेबाजी का मामला सामने आया है। यह नारेबाजी दिल्ली दंगों के आरोपी उमर खालिद और देशद्रोह के आरोपी शरजील इमाम के समर्थन में की गई।

रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह घटना रात के समय साबरमती हॉस्टल के बाहर हुई। इस दौरान वामपंथी छात्र संगठनों से जुड़े छात्रों ने प्रदर्शन किया और 'मोदी-शाह तेरी कब्र खुदेगी', 'अंबानी राज की कब्र खुदेगी, छूह की धरती पर' और 'अडानी की कब्र खुदेगी, छूह की धरती पर' जैसे नारे लगाए, जिसके बाद विवाद और गहरा गया।

बताया जा रहा है कि यह प्रदर्शन सुप्रीम कोर्ट द्वारा उमर खालिद और शरजील इमाम की जमानत याचिका खारिज किए जाने के विरोध में किया गया। प्रदर्शन के दौरान छात्रों ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ भी नारेबाजी की। गौरतलब है कि शरजील इमाम पर देशद्रोह का मामला दर्ज है। उस पर कथित तौर पर 'चिकन नेक' काटकर पूर्वोज़र भारत को देश से अलग करने की बात कहने का आरोप है। वहीं, उमर खालिद पर वर्ष 2020 के दिल्ली दंगों की साजिश में शामिल होने का मामला चल रहा है।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अभियोजन पक्ष के साक्ष्यों से यह संकेत मिलता है कि उमर खालिद और शरजील इमाम दिल्ली दंगों की साजिश रचने, लोगों को लामबंद करने और रणनीतिक दिशा-निर्देश देने में शामिल थे। इसके बाद अदालत ने दोनों की जमानत याचिका खारिज कर दी थी।

छूह में हुई नारेबाजी पर भाजपा नेताओं की कड़ी प्रतिक्रिया सामने आई है। मंत्री कपिल मिश्रा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'ङ्क' पर कहा कि जब नज़्सलियों, आतंकियों और दंगाइयों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, तो उनके समर्थक बौखलाए हुए हैं। वहीं, भाजपा नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि यह पूरी तरह गलत है। उन्होंने कहा कि पहले देशविरोधी गतिविधियां की जाती हैं और फिर उनके समर्थन में इस तरह के नारे लगाए जाते हैं। ऐसे लोगों और नारेबाजी करने वालों के खिलाफ सख़्त कार्रवाई होनी चाहिए।

उल्लेखनीय है कि छूह इससे पहले भी कई बार विवादों में रहा है। विश्वविद्यालय परिसर में पूर्व में भी आपज़िजनक नारेबाजी और विरोध प्रदर्शनों की घटनाएं सामने आ चुकी हैं। साबरमती हॉस्टल के बाहर हुई यह घटना एक बार फिर छूह को सुर्खियों में ले आई है।

कलिंग समाचार
THE KALINGA SAMACHAR
(A Hindi Daily News Paper)
PUBLISHED FROM ODISHA, JHARKHAND & CHATTISHGARH
FOR NEWS AND ADVERTISEMENT CONTACT
AT: QRS. NO. B/204, SECTOR-16
ROURKELA, PH. 0661-2646999
PRAKASH KUMAR DHAL (EDITOR)
E-mail: thekalingasamachar@gmail.com

विविध समाचार

रबी फसलों के स्थान पर औषधीय एवं मसाला लगायें चन्द्रशूर

चन्द्रशूर एक ऐसी रबी औषधीय फसल है, जो विभिन्न प्रकार की भूमियों में बहुत ही कम संसाधनों में व सीमित सिंचाई साधनों के साथ उगाई जा सकती है।

वानस्पतिक विवरण

चन्द्रशूर का वानस्पतिक नाम लेपीडियम सटाइवम है एवं यह कुसीफेरी कुल का सदस्य है। मध्यप्रदेश में इसकी खेती सफलतापूर्वक व्यावसायिक स्तर पर की जा रही है।

चन्द्रशूर के अन्य नाम

असारिया, हालिम आली आरिया आदि।

चन्द्रशूर का पौधा 30–60 सेमी ऊंचा होता है जिसकी उम्र 3–4 माह होती है। इसके बीज लाल भूरे रंग के होते हैं जो 2–3 मिमी लंबे बारीक तथा बेलनाकार होते हैं। पानी लगने पर बीज लसलसे हो जाते हैं। इसकी खेती रबी के मौसम में की जाती है। इसका पौधा अलसी से मिलता जुलता होता है।

औषधीय उपयोग

चन्द्रशूर लम्बाई बढ़ाने एवं सुदृढ़ता के लिये बच्चों को दूध के साथ दिया जाता है महिलाओं की प्रसव के उपरांत दूध न उतरने पर इसका सेवन अत्यंत उपयोगी माना गया है, पाचन संबंधी विकार, नेत्र पीड़ा, वात, मूत्र शुद्धि एवं प्रसव उपरांत टानिक के रूप में भी इसका प्रयोग आयुर्वेदिक चिकित्सा में किया जाता है। पशु आहार में चन्द्रशूर के उपयोग से दुधारू पशुओं में दुग्ध उत्पादन बढ़ जाता है।

अधिक उत्पादन के प्रमुख बिन्दु

भूमि

चन्द्रशूर वैसे तो सभी प्रकार की मिटटी में उगाया जा सकता है लेकिन उत्तम जल निकास वाली बुलई, दोमट मिट्टी जिसका पी.एच.मान सामान्य हो उपयुक्त होती है।

खेत की तैयारी

खेत में 3–4 बार जुताई कर पाटा से खेत को समतल कर लें। अंतिम जुताई में 6 टन गोबर खाद प्रति हेक्टेयर डाले यदि खरीफ की फसल में गोबर खाद डाली हो तो खाद डालने की आवश्यकता नहीं है।

बुआई समय

असिंचित क्षेत्रों में सितम्बर से अक्टूबर में तथा सिंचित क्षेत्रों में अक्टूबर–नवम्बर माह में बोनी की जाती है।

बीज दर एवं विधि

बीज दर 8 से 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से प्रर्याप्त होता है। कतारों से कतारों के बीच की दूरी 20 से 30 से.मी एवं बीज 1 से 1.5 से.मी. की गहराई पर डालें।

बीज उपचार

2 ग्राम थायरम , 1 ग्राम बाविस्टीन प्रति किलोग्राम बीज के मान से बीज को उपचारित करें।

रसायनिक खाद

20 किलोग्राम नत्रजन, 40 किलोग्राम स्फुर एवं 25 किलोग्राम जिंक सल्फेट प्रति हेक्टर के मान से बीज बुआई के पूर्व खेत में मिलायें।

खरपतवार रोकथाम

20 –25 दिन बाद खुरपी से खरपतवार निकालें।

सिंचाई

चन्द्रशूर की फसल असिंचित भूमि में ली जा सकती है किन्तु यदि 2 –3 सिंचाई उपलब्धता के आधार पर क्रमशः एक माह, दो माह, एवं ढाई माह पर सिंचाई करें तो यह लाभकारी होता है।

कटाई एवं गहाई

चन्द्रशूर की फसल 90 से 120 दिन के अंदर पक कर कटाई के लिये तैयार हो जाती है। पत्तियां जब हरे से पीली पड़ने लगे एवं फल में बीज लाल रंग का हो जाये तो यह समय कटाई के लिये उपयुक्त रहता है। हंसिये या हाथ से इसे उखाड़कर खलिहान में 2–3 दिन सूखने के लिये डाल दें फिर डंडे से पीटकर या ट्रैक्टर घुमाकर गहाई कर बीज को साफ कर लें।

उपज

असिंचित भूमि में 10–12 क्विंटल तथा सिंचित भूमि में 14–16 क्विंटल प्रति हेक्टर उपज प्राप्त होती है।

विपणन

नीमच, रतलाम, एवं मंदसौर, की मंडियों में यह बिक जाता है।

अधिक उत्पादन के प्रमुख बिन्दु

जलवायु

ठंडा सूखा वातावरण तथा खुले मौसम में ईसबगोल की फसल अच्छी होती है। फसल पकने के समय बादल नमी युक्त वातावरण अच्छा नहीं होता हैं ईसबगोल ऐसे समय में बोना चाहिये ताकि वह खुले मौसम में कट जावें अन्यथा पानी गिरने से इसका बीज खराब हो जाता है।

भूमि-

ईसबगोल सभी प्रकार की भूमि में पैदा किया जा सकता है परंतु उत्तम जल निकास वाली रेतीली दोमट भूमि इसके लिए उपयुक्त रहती है, जिसका पी एव मान 7 से 8 के बीच हो।

भूमि की तैयारी-

गोबर खाद भूमि में मिलाकर मिट्टी को बारीक भुरभुरी समतल निथार युक्त बनाकर सिंचाई की सुविधानुसार क्यारियों का आकार रखना चाहिये। बोनी लाईनों में या छिड़काव पद्धति से कर सकते है। लाइन से लाइन की दूरी 20 से मी रखना चाहिये।

उन्नत जातियां-

गुजरात ईसबगोल – 1, गुजरात ईसबगोल – 2 ये जातियां मध्यप्रदेश में 110 से 120 दिन में पककर तैयार होती हैं तथा 12 –14 क्विंटल प्रति हेक्टर उपज देती है। जवाहर ईसबगोल–4। यह 15 –17 क्विंटल प्रति हेक्टर उपज देती है।

बीज की मात्रा

4 से 5 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर से प्रर्याप्त होता है। कतारों से कतारों के बीच की दूरी 20 से 30 से.मी एवं बीज 1 से 1.5 से.मी. की गहराई पर बोएं।

बीज उपचार

2 ग्राम थायरम, 1 ग्राम बाविस्टीन प्रति किलोग्राम बीज से बीजोपचार किया जाता है।

बोनी का समय

ईसबगोल अक्टूबर में बोना चाहिये। बोनी पश्चात हल्की सिंचाई करना चाहिये ताकि बीज अपने स्थान से न हटे। 6 से 10 दिन में अंकुरण हो जाता है।

खाद की मात्रा

गोबर खाद 15 टन प्रति हेक्टेयर आखिरी जुताई के साथ भूमि में मिलायें।

रसायनिक खाद

50 किलोग्राम नत्रजन (50 प्रतिशत बोते समय एवं 50 प्रतिशत एक माह बाद खड़ी फसल में प्रथम सिंचाई के समय), 40 किलोग्राम स्फुर, 20 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टर बुआई के समय दें।

सिंचाई

पहली सिंचाई अंकुरण के लिये, द्वितीय सिंचाई 21 दिन बाद तथा तीसरी सिंचाई बालिया बनते समय देना चाहिये। ईसबगोल फसल मे कुल 3–4 सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। ध्यान रहे कि पानी खेत में न भरे अन्यथा फसल मर जायेगी।

निंदाई

खरपतवार नष्ट करने के लिये 1–2 निंदाई करवाना आवश्यक है अन्यथा उपज में कमी आ जाती है।

चन्द्रशूर की प्रमुख विशेषताएं

- चन्द्रशूर विभिन्न प्रकार की भूमियों में उगाया जा सकता है।
- फसल की यदि 1–2 बार ही सिंचाई की जाये तो भी अच्छी उपज प्राप्त हो जाती है।
- चन्द्रशूर की खड़ी फसल को पशु नहीं चरते।
- चन्द्रशूर की खाद/उर्वरक की मांग भी अत्यंत सीमित है।
- चन्द्रशूर को सामान्यतः कीट–बीमारी कम लगती है।
- चन्द्रशूर के पौधों की वृद्धि तेजी से होती है, अतः नींदा कम पनप पाता है।
- कम लागत में अपेक्षाकृत अधिक लाभ देने वाली फसल है।
- किसान भाईयों को रतलाम, नीमच, मन्दसौर तथा इंदौर में बाजार होने से विपणन की समस्या नही।
- चन्द्रशूर मालवरोध, चोट, अपच जैसी बीमारियों/ विकारों में भी उपयोगी दवा है।

कीड़े एवं बीमारी की रोकथाम

ईसबगोल मे मुख्य रुप से मोला (माहू) कीट का प्रकोप फूल अवस्था पर देखा गया है। कीट की रोकथाम के लिये मिथाइल डेमेटान 1 से 1.25 मिली दवा / लीटर पानी मे घोलकर छिड़काव करना चाहिये।

बीमारी

पावडरी मिल्डयू की रोकथाम के लिये 2 प्रतिशत घुलनशील सल्फर दो या तीन बार 15 दिन के अंतर मे छिड़काव करें।

डाउनी मिल्ड्यू बीमारी की रोकथाम के लिये 0.1 प्रतिशत बाविस्टीन का जैसे ही बीमारी दिखे छिड़काव करें तथा 8-10 दिन के अंतर से छिड़काव करें।

कटाई एवं गहाई

ईसबगोल फसल करीब 4-5 माह में पककर तैयार हो जाती है। जैसे ही पत्तियां पीली पड़ें और बालियां हरे रंग से भूरे रंग की हो जाये तो फसल पक गई। फसल सुबह के समय काटना चाहिये जिससे उसके दाने गिरते नहीं है। फसल काटने के बाद 1 से 2 दिन सुखा कर गहाई करना चाहिये। बीज और छिलका को अलग करने के लिये थ्रेशिंग मशीन का उपयोग करना चाहिये। उपज में लगभग 30 प्रतिशत भूसी निकलती है जो औषधि के काम आती है।

उपज

ईसबगोल की उपज करीब 12 -15 क्विंटल प्रति हेक्टयर आती है।

ईसबगोल

ईसबगोल एक औषधीय पौधा है। इसकी खेती सबसे अधिक भारत में पैदा की जाती है। राज्यों में – गुजरात पंजाब और उत्तर प्रदेश प्रमुख है जहां ईसबगोल एक नगद फसल के रूप में पैदा की जा रही है।

ईसबगोल एक छोटा तना रहित शाकीय पौधा होता है इसके बीज का छिलका (भूसी) का उपयोग औषधि के रूप में उपयोग किया जाता है। इसके बीज में क्यूसीलेज और एल्बोमीनियम पदार्थ सुरक्षित एवं अधिक मात्रा में पाया जाता है जो बीमारियों जैसे आमशय की जलन, मूत्र रोग, स्थाई कब्ज, आंव व दस्त, बवासीर आदि रोगों की रोकथाम के काम आते हैं।

कलिंग समाचार

संपादकीय

गुरूवार 08 जनवरी 2026

न्यायपालिका की साख का सवाल

भारत के प्रधान न्यायाधीश जस्टिस बीआर गवई ने कहा कि संविधान केवल शासन के लिए राजनीतिक दस्तावेज नहीं है, बल्कि यह %क्रांतिकारी वक्तव्य% है, जो गरीबी, असमानता और सामाजिक विभाजन से पीड़ित, औपनिवेशिक शासन के लंबे वर्षों से बाहर आ रहे देश को आशा की किरण दिखाता है। इटली के मिलान कोर्ट ऑफ अपील में बोलते हुए जस्टिस गवई ने कहा कि उन्हें यह कहते हुए गर्व महसूस हो रहा है कि भारतीय संविधान के निर्माता इसके प्रावधानों का मसौदा तैयार करते समय सामाजिक-आर्थिक न्याय की अनिवार्यता के प्रति गहराई से सचेत थे। जस्टिस गवई सोलह आने सच बात कह रहे हैं। संविधान निर्माताओं ने तो हर तरह की गैरबराबरी दूर करने और सबके लिए एक समान न्याय की जरूरत का सिद्धांत संविधान बनाते वक्त सामने रखा। लेकिन क्या मौजूदा वक्त में जिन लोगों पर संविधान का पालन करने और न्याय देने की जि मेदारी है, वे इस सिद्धांत पर कायम हैं, या विचलित हो चुके हैं, इसकी पड़ताल करनी होगी। बीते महीनों में दो ऐसे प्रकरण सामने आए हैं, जब जज की आसंदी पर बैठे लोगों की निष्ठा व इरादों पर सवालिया निशान लगे हैं। पिछले साल दिसंबर में इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस शेखर यादव ने विश्व हिंदू परिषद के कार्यक्रम में कथित तौर पर अल्पसं यकों के लिए ऐसी टिप्पणी की थी, जिस पर विवाद खड़ा हो गया था। बताया जाता है कि जस्टिस शेखर यादव ने कहा था कि देश को बहुसं यकों के हिसाब से चलना चाहिए। इस तरह के बयान को नफरती भाषण मानते हुए वरिष्ठ वकील और सांसद कपिल सिब्बल के नेतृत्व में 55 सांसदों ने 13 दिसंबर को ही उनके खिलाफ राज्यसभा स्पीकर यानी उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव सौंप दिया था। हालांकि जस्टिस यादव ने कहा था कि उनके बयान को तोड़मरोड़ कर पेश किया गया है। दूसरा मामला मार्च का है, जब 14 मार्च 2025 को जस्टिस यशवंत वर्मा के लुटियंस दिल्ली स्थित आधिकारिक आवास पर आग लगने की घटना हुई थी। आग बुझाने के लिए पहुंची दमकल विभाग की टीम और पुलिस ने मौक़े पर आधे जले हुए 500 रुपये के नोट और बड़ी मात्रा में नकदी देखी गई। इस मामले में बड़े भ्रष्टाचार के आरोप लगे तो जस्टिस यशवंत वर्मा ने इसे अपने खिलाफ बड़ी साजिश बताया। दोनों ही मामलों से न्यायपालिका पर आम आदमी का भरोसा हिल गया। क्योंकि एक तरफ अल्पसं यकों के लिए भेदभावपूर्ण रवैया और हिंदुत्ववादी ताकतों की तरफ झुकाव दिखा और दूसरी तरफ इंसाफ करने वाले के बेईमान रवैये की बू आई। अब जस्टिस वर्मा मामले में महाभियोग चलाने की तैयारी हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस वर्मा के घर नकदी मिलने के मामले पर तीन जजों की आंतरिक जांच समिति बनाई थी। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के मु य न्यायाधीश के जस्टिस शील नागु, हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के मु य न्यायाधीश जस्टिस जी एस संधावालिया और कर्नाटक हाई कोर्ट की जज जस्टिस अनु शिवरामन की इस समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है, जिसमें कहा गया है कि 14 मार्च को दिल्ली में उनके सरकारी आवास में आग लगने के दौरान वहां नकदी मिलने का मतलब है कि उन पर इसकी ज़ि मेदारी है। अब सरकार ने संसद के आगामी मानसून सत्र में जस्टिस वर्मा के खिलाफ़ महाभियोग प्रस्ताव लाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। बता दें कि इस मामले में जांच पैनल ने 55 गवाहों के बयान दर्ज किए, जिनमें से कम से कम 10 गवाहों ने पुष्टि की कि उन्होंने जस्टिस वर्मा के आवास पर आधे जले हुए या पूरी तरह जले हुए नोट देखे थे। पैनल ने कहा कि आधे जले हुए नोटों की मौजूदगी और उनका आवास पर पाया जाना गंभीर सवाल उठाता है। यह नकदी के आने और उसके इस्तेमाल पर संदेह पैदा करता है। रिपोर्ट के अनुसार जस्टिस वर्मा ने न तो पुलिस में शिकायत दर्ज कराई और न ही अपने वरिष्ठ न्यायिक अधिकारियों को इसकी सूचना दी। पैनल ने इसे अनुचित आचरण और %न्यायिक कर्तव्यों के प्रति लापरवाही माना है और महाभियोग की सिफारिश की है। इस मामले में कपिल सिब्बल ने कहा है कि कुछ वीडियो और मीडिया में आई जले नोटों की बातों को बिना जांच के आधार नहीं बनाया जा सकता।

रिजर्व बैंक दर में कटौती का अर्थव्यवस्था पर बहुत कम प्रभाव पड़ेगा

नन्तू बनर्जी

देश की वर्तमान आर्थिक वृद्धि दर को अन्य प्रमुख विश्व अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में काफी अच्छा माना जाता है, लेकिन दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले देश की आजीविका को बेहतर बनाने के लिए इसे कई वर्षों तक लगातार बनाये रखने और विस्तारित करने की आवश्यकता है। भारत में प्रति व्यक्ति खपत अन्य प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में काफी कम है।

पिछले दो वर्षों में देश की उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति दर 3.20 प्रतिशत के आसपास मंडरा रही है। ऐसे समय में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंक दर में 50 आधार अंकों की कटौती करने का नवीनतम निर्णय, जो इस वर्ष फरवरी से लगातार तीसरी कटौती है,समझ में आने लायक बात है। हालांकि, ऐसा लगता है कि यह गलत समय पर आया है क्योंकि यह भारत की अर्थव्यवस्था की अप्रैल से सितंबर तक के सामान्य वार्षिक कम कामकाज वाली छमाही के बीच में आया है, और कृषि उत्पादनों की कीमतें बढ़ रही हैं।

नियमित मानसून के बाद मौजूदा गर्मी के मौसम में दर में कटौती से उधार लेने और निवेश को बढ़ावा मिलने की संभावना नहीं है। ऐसा कभी हुआ भी नहीं। रिजर्व बैंक को भी उ मीद नहीं है कि विकास अनुमान पिछले वर्ष के लगभग 6.4 प्रतिशत के स्तर से आगे बढ़ेगा। यह निर्णय बैंकिंग उद्योग के सावधि जमा जुटाने के प्रयास को अस्थिर कर सकता है। आम तौर पर, बैंक दर का उपयोग आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए मौद्रिक नीति उपकरण के रूप में किया जाता है। यदि वे आर्थिक विकास को और बढ़ावा देने में मदद नहीं करते हैं, तो उधार दरों को कम क्यों किया जाये? विश्व बैंक की नवीनतम रिपोर्ट ने चालू वर्ष के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर को घटाकर 6.3 प्रतिशत कर दिया है।

हालांकि देश की वर्तमान आर्थिक वृद्धि दर को अन्य प्रमुख विश्व अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में काफी अच्छा माना जाता है, लेकिन दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले देश की आजीविका को बेहतर बनाने के लिए इसे कई वर्षों तक लगातार बनाये रखने और विस्तारित करने की आवश्यकता है। भारत में प्रति व्यक्ति खपत अन्य प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में काफी कम है। भारत की प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद 2025 में केवल 2,880 के आसपास होने का अनुमान है। यह भारत को नि न मध्यम आय वाले देशों. की सूची में सबसे निचले पायदान पर रखता है।

प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में, जापान की प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद 33,900 है, जो भारत की तुलना में 11 गुना अधिक है। संयुक्त राज्य अमेरिका की प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद 89,000 है। भारत की शीर्ष 15 प्रतिशत आबादी और बाकी लोगों के खर्च करने के तरीकों में बहुत बड़ा अंतर है। भारत में खपत आबादी के एक छोटे से हिस्से द्वारा संचालित होती है, जबकि अधिकांश आबादी आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं पर खर्च करती है, जो एक महत्वपूर्ण आय असमानता को उजागर करती है। देश में बेरोजगारी और अल्परोजगार की दरें काफी अधिक हैं। यह बताता है कि रिजर्व बैंक द्वारा बैंक दर में बार-बार की गयी कटौती सार्वजनिक खपत और घरेलू निवेश को बढ़ाने में विफल रही है।

वर्तमान परिस्थितियों में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बार-बार की गयी दरों में कटौती से बचत और वाणिज्यिक बैंक के प्रदर्शन दोनों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। यह अनुमान लगाना गलत हो सकता है कि कम बैंक दरें पारंपरिक बैंक सावधि जमाकर्ताओं को उच्च जोखिम वाले शेयर बाजार साधनों में बचत करने के लिए प्रेरित करेंगी। वैसे भी, देश की आबादी का केवल एक छोटा प्रतिशत ही शेयर बाजार में सक्रिय रूप से निवेश करता है। यह सं या केवल पांच प्रतिशत के आसपास होने का अनुमान है। आम तौर पर पसंदीदा निवेश के रास्ते सावधि जमा और रियल एस्टेट हैं।

अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करने के बजाय, बार-बार केंद्रीय बैंक की दरों में कटौती से मुद्रास्फीति, कमजोर मुद्रा और बचत पर कम रिटर्न सहित नकारात्मक परिणाम होने की संभावना है। वे उच्च प्रतिफल की चाह रखने वाले निवेशकों द्वारा परिसंपत्ति बुलबुले और जोखिम उठाने का कारण भी बन सकते हैं। जबकि कम दरें उधार लेने और निवेश को प्रोत्साहित कर सकती हैं, वे सावधानी से प्रबंधित न किये जाने पर अस्थिर विस्तार को भी जन्म दे सकती हैं। कम दरें विदेशी पूंजी निवेशकों को भी हतोत्साहित करती हैं। कम ब्याज दरें किसी देश की मुद्रा को विदेशी निवेशकों के लिए कम आकर्षक बना सकती हैं, तथा संभावित रूप से अन्य मुद्राओं के मुकाबले इसके मूल्य को कमजोर कर सकती हैं। लगभग पूरी दुनिया में, सरकारें ब्याज दरों में कटौती करने के लिए केंद्रीय बैंकों पर दबाव डालती हैं। उस दबाव की सीमा और प्रकृति अलग-अलग होती है।

भारत में, सरकार केंद्रीय वित्त मंत्रालय में सेवानिवृत्त करियर नौकरशाह को देश के केंद्रीय बैंक के गवर्नर के रूप में नियुक्त करना पसंद करती है क्योंकि इसे अक्सर अपने राजनीतिक एजंडे को आगे बढ़ाने के लिए रिजर्व बैंक के प्रमुख अर्थशास्त्री से निपटना असहज लगता है।

सरकार अक्सर देश के लिए अल्पकालिक लाभों पर ध्यान केंद्रित करती है, अक्सर इसकी लोकप्रियता के एक बेंचमार्क के रूप में, जबकि केंद्रीय बैंक पारंपरिक रूप से अत्यधिक खर्च को रोककर मुद्रास्फीति को रोकने के बारे में चिंतित रहता है। यह प्रवृत्ति मुक्त लोकतांत्रिक दुनिया भर में आम है, जो अनिवार्य रूप से कार्यकारी शाखा और केंद्रीय बैंक के बीच एक निश्चित मात्रा में संघर्ष की ओर ले जाती है। संयुक्त राज्य अमेरिका में, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्र प पहले से ही इस परंपरा का पालन करते देखे जा रहे हैं।

अपने पहले कार्यकाल के दौरान, अमेरिकी केंद्रीय बैंक या फेडरल रिजर्व सिस्टम (जिसे आमतौर पर %फेड. कहा जाता है) ने ब्याज दरें बढ़ाकर और आर्थिक गतिविधियों को प्रतिबंधित करके राष्ट्रपति ट्र प की नाराजगी मोल ली थी। राष्ट्रपति ट्र प को अपने मौजूदा कार्यकाल में भी यही समस्या हो रही है। फेड ने दरें स्थिर रखने का फैसला किया है, जिस पर राष्ट्रपति ने तीखी फटकार लगाई है।

भारत में, उधार दरों में कटौती अकेले घरेलू उत्पादन में निवेश में मदद नहीं करने जा रही है, भले ही इससे खपत की मांग बढ़े। डर यह है कि फंड की कम लागत से माल आयात में और वृद्धि हो सकती है। वास्तव में, बढ़ते माल आयात भारत के साथ प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं, बावजूद देश की जीडीपी वृद्धि दर विश्व बैंक के %नि न मध्यम आय. समूह में देश की स्थिति के। भारत लगातार संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, जर्मनी, जापान, यूनाइटेड किंगडम, नीदरलैंड, फ्रांस, इटली, दक्षिण कोरिया, कनाडा, स्पेन, ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम और स्विट्जरलैंड जैसे %उच्च आय समूह. देशों के साथ प्रतिस्पर्धा कर रहा है ताकि दुनिया के शीर्ष 15 माल आयात करने वाले देशों में से एक बना रहे। भारत फ्रांस के बाद सूची में आठवें स्थान पर है और इटली, दक्षिण कोरिया, कनाडा, स्पेन, ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम और स्विट्जरलैंड से आगे है।

बैंक दरों के साथ रिजर्व बैंक के हेरफेर से घरेलू माल उत्पादन में तेजी लाने, आयात में कटौती करने और निर्यात को बढ़ावा देने में विफलता मिली है। इस प्रकार, सरकार से मजबूत नीति समर्थन की अनुपस्थिति में घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने में भारतीय केंद्रीय बैंक की भूमिका कुछ हद तक अस्पष्ट बनी हुई है। भारत की आर्थिक विकास दर और मुद्रास्फीति के हाल के इतिहास को देखते हुए, इस स्तर पर रिजर्व बैंक द्वारा बार-बार दरों में कटौती करना अनावश्यक लग सकता है, अगर भ्रमित करने वाला न भी हो। पिछले 10 वर्षों में औसत मुद्रास्फीति दर लगभग 5.85 प्रतिशत रही है। 2016, 2017, 2018 और 2029 में मुद्रास्फीति दर चार प्रतिशत से कम थी। ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स के अनुसार, 2015, 2020, 2021 और 2022 में यह दर अधिक रही, जो 2015 में 6.45 प्रतिशत से लेकर 2021 में 5.53 प्रतिशत तक रही। मासिक मुद्रास्फीति दर में उतार-चढ़ाव रहा है, जो नवंबर 2013 में 12.17 प्रतिशत के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया और जून 2017 में 1.54 प्रतिशत के रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गया।

ईरान में तख्तापलट के लिए छेड़ा गया युद्ध

सर्वमित्रा सुरजन

रजा पहलवी ईरान के आखिरी शाह मोह मद रजा पहलवी के सबसे बड़े बेटे हैं। शाह मोह मद रजा पहलवी के शासन को 1979 की इस्लामी क्रांति के दौरान उखाड़ फेंका गया था। पहलवी खानदान ने तब ईरान छोड़ दिया था और सत्ता अयातुल्लाह रुहोल्लाह खुमैनी के हाथों में आ गई थी, जिन्होंने ईरान में इस्लामी गणराज्य की स्थापना की थी। सत्ता संभालने से पहले खुमैनी पेरिस में थे।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कनाडा में जी-7 शिखर स मेलन को बीच में ही छोड़कर जब वाशिंगटन के लिए रवाना हो गए थे, तभी से कयास लग रहे थे कि क्या अब अमेरिका इस जंग में सीधे उतरेगा। अमेरिका ने अब तक ईरान से सीधी लड़ाई का ऐलान तो नहीं किया है, लेकिन इजराइल-ईरान युद्ध के बीच ट्रंप ने ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई को लेकर अब तक का सबसे बड़ा बयान दिया है, जो किसी लड़ाई से कम नहीं है। ट्रंप ने खामेनेई का नाम लिए बगैर सोशल मीडिया पर सुप्रीम लीडर% लिखते हुए पोस्ट किया है। ट्रंप ने कहा है कि हम अच्छी तरह से जानते हैं कि तथाकथित %सुप्रीम लीडर% कहां छिपे हैं. वह एक आसान निशाना हैं लेकिन वहां सुरक्षित हैं. हम उन्हें मारेंगे नहीं, कम से कम अभी तो नहीं. मगर, हम नहीं चाहते कि मिसाइलें नागरिकों या अमेरिकी सैनिकों पर दागी जाएं. हमारा धैर्य खत्म होता जा रहा है।इसके बाद एक दूसरी पोस्ट में ट्रंप ने अनकंडीशनल सरेंडर लिखा, यानी ट्रंप ने ईरान से बिना शर्त सरेंडर करने के लिए कहा है। इधर डोनाल्ड ट्रंप आयतुल्लाह खामेनेई को अभी नहीं मारने की बात कह रहे हैं, उधर ईरान पर हमला बोलने वाले इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू कह रहे हैं कि ख़ामेनेई की मौत %संघर्ष को बढ़ाने के बजाय, उसे ख़त्म करने का काम करेगी।%

अलग-अलग मीडिया रिपोर्ट्स से यह अनुमान लग रहा है कि इजरायल का बस चले तो वह आज खामनेई को मार दे, लेकिन अमेरिका ने अभी इस पर वीटो लगा रखा है, यानी अमेरिका की मंजूरी मिलने के बाद ही इजरायल यह बड़ा कदम उठाएगा। इस बीच बेंजामिन नेतन्याहू और ईरान के निर्वासित क्राउन प्रिंस रजा पहलवी के बयानों से जाहिर हो रहा है कि इजरायल ने ईरान पर परमाणु हथियार बनाने से रोकने के नाम पर जो हमला बोला है, वह असल में एक मुखौटा है। इसके पीछे असली वजह शायद ईरान में फिर से शाह के शासन को बहाल करना है। कहा जा रहा है कि इजराइल और अमेरिका के समर्थन से रजा पहलवी के लिए ईरानी गद्दी संभालने के लिए तैयारी शुरू हो गई है। रजा पहलवी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में ऐलान किया कि ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई %अंडरग्राउंड होकर छिप गए हैं% और %इस्लामिक गणराज्य ध्वस्त होने की प्रक्रिया में है।% उन्होंने अयातुल्ला अली खामेनेई की तुलना चूहे से कर डाली। रजा पहलवी ने तेहरान में शासन परिवर्तन का आह्वान करते हुए कहा कि इस्लामिक गणराज्य ढह रहा है और ईरानी लोगों के लिए ईरान को फिर से हासिल करने का समय आ गया है। उन्होंने इसे एक अपरिवर्तनीय क्षण बताया। उन्होंने लिखा, %इस्लामी गणराज्य का अंत ईरानी राष्ट्र के खिलाफ उसके 46 साल के युद्ध का अंत है। अब उठने का समय है।% ईरानी क्राउन प्रिंस ने लोगों को संबोधित करते हुए एक वीडियो भी पोस्ट किया है, जिसमें उन्होंने इसे ईरानी लोगों के लिए ऐतिहासिक मोड़ बताया। और कहा कि भविष्य उज्ज्वल है और साथ मिलकर हम इतिहास के इस तीखे मोड़ से गुजरेंगे।

गौरतलब है कि पहलवी पहले भी खामेनेई के शासन को उखाड़ फेंकने का आह्वान कर चुके हैं। निर्वासित क्राउन प्रिंस अब ईरान के लोगों को ये भी बता रहे हैं कि उनके पास देश के भविष्य के लिए योजना है। उन्होंने कहा, ईरान गृहयुद्ध या अस्थिरता में नहीं उतरेगा। मौजूदा शासन की हार के बाद पहले 100 दिनों के संक्रमण काल के लिए ईरानी लोगों द्वारा और ईरानी लोगों के लिए एक राष्ट्रीय और लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना के लिए हम तैयार हैं, ऐसा दावा पहलवी ने किया है। उन्होंने सेना, पुलिस और ईरानी कर्मचारियों को भी संदेश दिया और खामेनेई के शासन से अलग हो जाने को कहा।

रजा पहलवी ईरान के आखिरी शाह मोह मद रजा पहलवी के सबसे बड़े बेटे हैं। शाह मोह मद रजा पहलवी के शासन को 1979 की इस्लामी क्रांति के दौरान उखाड़ फेंका गया था। पहलवी खानदान ने तब ईरान छोड़ दिया था और सत्ता अयातुल्लाह रुहोल्लाह खुमैनी के हाथों में आ गई थी, जिन्होंने ईरान में इस्लामी गणराज्य की स्थापना की थी। सत्ता संभालने से पहले खुमैनी पेरिस में थे, क्योंकि अमेरिका से नज़दीकी संबंधों का विरोध करने के चलते शाह ने उन्हें देश से निष्कासित कर दिया था। लेकिन जब शाह मोह मद रजा पहलवी को ईरान छोड़ना पड़ा तो फिर इस्लामी गणराज्य की स्थापना हो गई और शासन की बागडोर मौलवियों के हाथ में आई। इन्हीं मौलवियों में एक नाम अली ख़ामेनेई का भी है, जो बहुत कम समय में खुमैनी के सबसे क़रीबी सहयोगियों में शामिल हो गए थे।

यह समझना जरूरी है कि खुमैनी के बाद आयतुल्लाह अली ख़ामेनेई आखिर इतने महत्वपूर्ण क्यों हो गए कि इजरायल और अमेरिका दोनों उनकी जान के पीछे पड़े हैं। खामनेई उस दौर में बड़े हो रहे थे, जब ईरान में पहलवी शासन था और अपनी धर्मनिरपेक्ष सोच की वजह से शाह धार्मिक व्यक्तियों को तरजीह नहीं देते थे। खामनेई 11 बरस की छोटी उम्र में ही मौलवी बन गए थे और फिर जल्द ही खुमैनी के समर्थन में काम करना शुरू कर दिया। ईरान में इस्लामी शासन स्थापित करने वाले संदेश देश के भीतर फैलाने के प्रयास में खामनेई को छह बार गिर तार भी किया गया। उन पर दो बार जानलेवा हमले भी हुए। जब खुमैनी के हाथ में सत्ता आई तो ख़ामेनेई को देश का उप-रक्षा मंत्री नियुक्त किया गया. इस दौरान उन्होंने इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर (आईआरजीसी) को संगठित करने में अहम भूमिका निभाई, जो इस समय ईरान की सबसे शक्तिशाली संस्थाओं में से एक है। 1989 में जब खुमैनी की मौत हुई तो ख़ामेनेई को ईरान का अगला सुप्रीम लीडर नियुक्त किया गया। अब इसी सुप्रीम लीडर को इजरायल ने अपने निशाने पर रखा है। एक तरफ रजा पहलवी ने ईरान की जनता को संदेश दे दिया है कि जल्द ही खामनेई की सत्ता का अंत होगा, तो दूसरी तरफ बेंजामिन नेतन्याहू ने भी ईरानी अवाम को अंग्रेजी में सीधे संबोधित किया और ईरानियों से अपील की कि अब समय आ गया है, जब वे %शैतानी और दमनकारी शासन% के ख़िलाफ़ उठ खड़े हों। नेतन्याहू ने कहा, %इसराइली सैन्य अभियान आपके लिए आज़ादी हासिल करने का रास्ता साफ़ कर रहा है। ये पूरा घटनाक्रम बता रहा है कि ख़ामेनेई को किसी भी तरह रास्ते से हटाना इजरायल और अमेरिका का मिशन है, हालांकि खामनेई अब भी खुलकर इजरायल के अस्तित्व को मिटाने की बात करते रहे हैं। वो लंबे समय से इजरायल को पश्चिम एशियाई क्षेत्र का एक ऐसा %कैंसरग्रस्त ट्यूमर% बताते रहे हैं, जिसे उखाड़ फेंकना ज़रूरी है और उनके मुताबिक़ ये होकर रहेगा।

इधर इजरायल में अब नेतन्याहू के इस कदम के खिलाफ आवाज उठने लगी है। ईरान की रेडियो सेवा पार्स टुडे के मुताबिक इज़रायली सुरक्षा एवं सैन्य विशेषज्ञ योसी मेलमैन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म %एक्स% पर एक संदेश में इजरायली शासन के नेताओं को सलाह दी कि तेहरान से युद्धविराम की भीख मांगने से पहले इस पागलपन को रोकें। मेलमैन ने कहा शिया ऐतिहासिक रूप से पीड़ा सहन करने के लिए तैयार रहते हैं। मैंने उनकी बलिदान की इच्छा को याद किया, जैसा कि इराक के साथ आठ साल के युद्ध में देखा गया था। मेरी सलाह है कि हम नुकसान को कम से कम करें और इस पागलपन को रोकने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति %डोनाल्ड ट्र प% के माध्यम से एक उचित समझौते का सहारा लें- नहीं तो हमें युद्धविराम के लिए गिड़गिड़ाना पड़ेगा और ईरान मना कर देगा।%

वहीं इजरायल के अख़बार हाआरेत्ज़ ने ईरानी मिसाइलों के सामने अपनी वायु रक्षा प्रणालियों की विफलता को स्वीकार किया और नेतन्याहू सरकार से तुरंत अपनी सैन्य दादागिरी और युद्ध भड़काने की कार्रवाई को समाप्त करने का आग्रह किया। हाआरेत्ज़ ने लिखा- %इज़रायल की वायु रक्षा प्रणालियां ईरान के उन्नत मिसाइलों का मुकाबला करने में विफल रही हैं। इज़रायली सेना और सरकार के कमांडरों को सबक लेना चाहिए और बेहद कठिन और अवांछित घटनाक्रम से बचने के लिए युद्ध को रोकना चाहिए। इस पूरे घटनाक्रम से यही समझ आ रहा है कि इजरायल और अमेरिका परमाणु हथियारों को केवल बहाना बना रहे हैं और किसी भी तरह ईरान में सत्ता पलटने की तैयारी में हैं। ठीक वैसे ही जैसे ईराक में सद्दाम हुसैन को मारकर त तापलट किया गया था। हालांकि इस बार अमेरिका के लिए यह खेल आसान नहीं होगा।

विविध समाचार

पंजाब में अब १० लाख तक मिलेगा मुफ्त इलाज, सरकार ने स्वास्थ्य योजना पर लगाई मुहर

चंडीगढ़ ०७/०१ (संवाददाता): पंजाब के निवासियों के लिए नए साल के तोहफे के रूप में मुख्यमंत्री मान ने स्वास्थ्य विभाग को जनवरी माह से मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना शुरू करने की मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत राज्य के प्रत्येक परिवार को 10 लाख रुपये तक का नकद–रहित इलाज सुनिश्चित किया जाएगा। गुरुवार को स्वास्थ्य विभाग की बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री स भगवंत सिंह मान ने कहा कि मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरुआत राज्य के लोगों को बिना एक भी पैसा खर्च किए व्यापक स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा, यह योजना विश्व–स्तरीय स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने और लोगों को 10 लाख रुपये तक का नकद–रहित इलाज सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सरकार द्वारा शुरू की गई एक ऐतिहासिक पहल है। पंजाब देश का पहला ऐसा राज्य होगा, जहां हर परिवार को 10 लाख रुपये तक का नकद–रहित इलाज मिलेगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना पंजाब सरकार की एक प्रमुख योजना है, जिसका उद्देश्य राज्य के सभी पात्र निवासियों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं के लिए वित्तीय सुरक्षा और आसान पहुंच प्रदान करना है।

उन्होंने कहा, यह योजना सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज की दिशा में एक अहम कदम है, जिसके अंतर्गत प्रत्येक नामांकित परिवार प्रति वर्ष 10 लाख रुपये तक का नकद–रहित चिकित्सकीय उपचार प्राप्त कर सकेगा। मुख्यमंत्री मान ने कहा कि इस योजना के तहत स्वास्थ्य सेवाओं तक सभी निवासियों की आसान पहुंच सुनिश्चित की गई है। इसके अंतर्गत पंजाब और चंडीगढ़ के सूचीबद्ध सरकारी एवं निजी अस्पतालों के व्यापक नेटवर्क में गंभीर बीमारियों, बड़ी सर्जरी, आईसीयू, क्रिटिकल केयर और जीवन–रक्षक उपचार की सुविधा उपलब्ध होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि योजना का मुख्य उद्देश्य सूचीबद्ध अस्पतालों में नकद–रहित और कागज–रहित स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित करने के साथ–साथ द्वितीयक और तृतीयक स्वास्थ्य देखभाल पर होने वाले भारी खर्च को कम करना है। उन्होंने कहा, यह योजना शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच को मजबूत करेगी तथा डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से समयबद्ध शिकायत निवारण और लाभार्थियों को त्वरित सहायता भी सुनिश्चित की जाएगी। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि इस योजना के अंतर्गत अस्पताल में भर्ती होने पर होने वाले खर्च, सर्जरी एवं चिकित्सकीय प्रक्रियाएं, आईसीयू और गहन देखभाल सेवाएं, बीमारियों की जांच, दवाइयां, स्वीकृत पैकेजों के अनुसार उपयोग में आने वाली सामग्री, अस्पताल में भर्ती होने से पहले और बाद के खर्चों सहित सभी संबंधित व्यय कवर किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले एक परिवार केवल 5 लाख रुपये तक का इलाज करा सकता था, लेकिन अब यह सीमा बढ़ाकर 10 लाख रुपये कर दी गई है। उन्होंने आगे कहा कि पंजाब का हर नागरिक कृ चाहे वह सरकारी कर्मचारी हो या पेंशनभोगी कृ इस मुफ्त स्वास्थ्य योजना का लाभ लेने का हकदार होगा। इस योजना के लिए किसी प्रकार की आय सीमा निर्धारित नहीं की गई है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि इस योजना के तहत कोई भी नागरिक किसी भी सरकारी अस्पताल या सूचीबद्ध निजी अस्पताल में अपना मुफ्त इलाज करवा सकेगा। उन्होंने कहा कि अब पंजाब में किसी भी नागरिक को आर्थिक तंगी के कारण इलाज से वंचित नहीं रहना पड़ेगा। मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिए कि जनहित में इस महत्वाकांक्षी योजना को सुचारू रूप से लागू करने के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं समयबद्ध रूप से सुनिश्चित की जाएं। बिल खुद अस्पताल क्लेम करेगा, मरीज को रुपए नहीं देना होगारू सरकार के मुताबिक यह एक कैशलेस सुविधा है। इसमें पैसे जमा करवाने की जरूरत नहीं है और न ही इलाज के दौरान कोई पैसा खर्च करना होगा। मरीज इलाज कराएगा और खर्चा सरकार सीधे अस्पताल को देगी। मरीज को कोई बिल या किसी तरह का हिसाब–किताब देने की जरूरत नहीं है। अस्पताल अपने स्तर पर सरकार को इसका क्लेम भरेंगे। बिल वगैरह भी वही उपलब्ध कराएंगे। पूरे परिवार का एक ही कार्ड बनेगारू सरकार के मुताबिक पूरे परिवार का एक फ्लोटर कार्ड बनेगा। इसकी लिमिट 10 लाख रुपए प्रति वर्ष होगी। इससे परिवार के सभी सदस्य तय राशि तक का इलाज करवा सकेंगे। 10 लाख रुपए तक के इलाज की राशि एक व्यक्ति के लिए नहीं, बल्कि पूरे परिवार के लिए है।

अकाली दल को 2019 तक "बाल दिवस" नाम बिल्कुल सही लगता था, लेकिन गठबंधन टूटने के बाद वही नाम गलत लगने लगा : बलियावाल

चंडीगढ़ ०७/०१ (संवाददाता): पिछले कुछ दिनों से "वीर बाल दिवस" के नाम को लेकर चल रहे विवाद पर भाजपा पंजाब के प्रवक्ता प्रितपाल सिंह बलियावाल ने शिरोमणि अकाली दल और बठिंडा से सांसद श्रीमती हरसिमरत कौर बादल को जवाब दिया है। बलियावाल ने श्रीमती हरसिमरत कौर बादल के एक पुराने ट्वीट को सबूत के तौर पर पेश करते हुए कहा कि साहिबजादों की शहादत को समर्पित "बाल दिवस" मनाने की वकालत स्वयं हरसिमरत कौर बादल ने वर्ष 2019 में अपने ट्वीट के माध्यम से की थी, लेकिन भाजपा से गठबंधन टूटने के बाद अकाली दल के सुर बदल गए। बलियावाल ने सवाल उठाते हुए कहा कि अकाली दल को 2019 तक केवल "बाल दिवस" नाम ही सही लगता था, लेकिन अब उसमें "वीर" शब्द जुड़ने से वह नाम गलत कैसे हो गया? उन्होंने आगे कहा कि इससे पहले वर्ष 2018 में भी दिल्ली के विज्ञान भवन में दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी द्वारा आयोजित कार्यक्रम में सुखबीर सिंह बादल ने अकाली दल की नेतृत्व की ओर से "बाल दिवस" नाम रखने पर सहमति दी थी, लेकिन अब वे अपने ही रुख से मुकर गए हैं। बलियावाल ने कहा कि जब अकाली दल और भाजपा का गठबंधन था, तब धार्मिक, किसान और पंजाब से जुड़े हर मुद्दे पर अकाली दल से सलाह ली जाती थी और उनकी सहमति के बाद ही फैसले लागू किए जाते थे। इसके बावजूद अकाली दल की नेतृत्व ने हमेशा हमारी नेतृत्व के साथ विश्वासघात किया और अपनी राजनीति चमकाने के लिए भाजपा को पंजाब विरोधी दिखाने की कोशिश की, ताकि उनकी राजनीतिक जमीन बनी रहे और भाजपा पंजाब में पैर न पसार सके। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमेशा सिख इतिहास, सिख परंपराओं और साहिबजादों की महान शहादत को सर्वोच्च सम्मान दिया है। "वीर बाल दिवस" की घोषणा पूरी दुनिया के सामने इस महान बलिदान की मान्यता का प्रतीक है। अंत में बलियावाल ने शिरोमणि अकाली दल और उसकी पूरी नेतृत्व से अपील की कि वे धार्मिक मुद्दों पर राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश न करें और अपनी ही पहले की गई मांग की सच्चाई को स्वीकार करें। साहिबजादों के शहीदी दिवसों पर नाम को लेकर राजनीति नहीं की जानी चाहिए।

चंडीगढ़ जिला कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी के बाद मचा हडकंप, खाली कराया गया परिसर

चंडीगढ ०७/०१ (संवाददाता): सेक्टर–43 स्थित जिला अदालत परिसर को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो गईं। सूचना मिलते ही एहतियातन कोर्ट परिसर को तत्काल खाली कराया गया और दोनों मुख्य गेट बंद कर दिए गए। इसके साथ ही किसी को भी अदालत परिसर के अंदर प्रवेश की अनुमति नहीं दी जा रही है। पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बम स्क्वॉड और अन्य सुरक्षा एजेंसियां मौके पर पहुंचीं। पूरे परिसर को चारों ओर से सील कर एंट्री–एग्जिट प्वाइंट्स पर कड़ी निगरानी शुरू कर दी गई है। कोर्ट के भीतर भी सघन तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। सूत्रों के अनुसार धमकी अदालत की आधिकारिक मेल आईडी पर ईमेल के जरिए भेजी गई है। ईमेल में धमकी देने वाले ने ड्रोन के माध्यम से बम विस्फोट कर कोर्ट को उड़ाने की बात कही है। मामले की जानकारी मिलते ही एसएसपी कार्यालय को सूचित किया गया, जिसके बाद थाना सेक्टर–36 और सेक्टर–39 समेत पुलिस टीमें मौके पर पहुंच गईं।

पंजाब में 1,350 करोड़ की लागत से बनेंगे 3,100 स्टेडियम, सीएम मान ने तय की जून 2026 की डेडलाइन

चंडीगढ़ ०७/०१ (संवाददाता): मुख्यमंत्री स. भगवंत सिंह मान ने आज खेल और युवा सेवाएं विभाग के साथ उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक के दौरान पंजाब के खेल बुनियादी ढांचे के नवीनीकरण के लिए स्पष्ट, समयबद्ध निर्देश जारी करते हुए अधिकारियों को प्रदेश भर में 1,350 करोड़ रुपए की लागत से बनाए जा रहे 3,100 स्टेडियमों का कार्य जून 2026 तक पूरा करने के निर्देश दिए। इस दौरान मुख्यमंत्री द्वारा एक व्यापक पैकेज की भी शुरुआत की गई जिसमें लगभग 3,000 स्थानों पर अत्याधुनिक जिम स्थापित करना, 50 करोड़ रुपए की लागत से 17,000 खेल किटों का वितरण, एक व्यापक खेल पोर्टल की शुरुआत और 43 करोड़ रुपए की लागत से एक नए युवा भवन का निर्माण शामिल है। उन्होंने कहा कि सरकार का मुख्य उद्देश्य पंजाब के युवाओं की असीम ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में लगाना और उन्हें नशे के खतरे से दूर रखना है। आज यहां खेल और युवा सेवाएं विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि नई खेल नीति 2023 के अनुसार प्रदेश भर के गांवों में ये स्टेडियम बनाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इन स्टेडियमों पर 1350 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे जिनमें बाड़, गेट, जॉगिंग ट्रैक, समतल खेल का मैदान, पेड़, वॉलीबॉल कोर्ट, स्टोर और अन्य सुविधाएं शामिल हैं। भगवंत सिंह मान ने कहा कि इन स्टेडियमों का कार्य निर्धारित समय के अंदर पूरा किया जाना चाहिए और साथ ही हर हालत में कार्यों की गुणवत्ता भी सुनिश्चित की जानी चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि युवाओं की ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में ले जाने के लिए प्रदेश भर में लगभग 3000 स्थानों पर अत्याधुनिक जिम स्थापित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि पहले चरण के तहत प्रदेश भर में 1000 स्थानों पर 35 करोड़ रुपए की लागत से ऐसे अत्याधुनिक जिम स्थापित किए जाएंगे। भगवंत सिंह मान ने कहा कि इन जिमों में वेट लिफ्टिंग सेट, बेंच, डंबल सेट, केटलबेल सेट, रैक, फ्लोर मैट और अन्य कई अत्याधुनिक उपकरण शामिल होंगे। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि राज्य सरकार द्वारा 50 करोड़ रुपए की लागत से खिलाड़ियों को 17000 खेल किटें वितरित की जाएंगी। उन्होंने कहा कि इन किटों में वॉलीबॉल और फुटबॉल (प्रत्येक के लिए तीन वॉलीबॉल और फुटबॉल तथा दो नेट), क्रिकेट के लिए दो बैट, विकेट, छह टेनिस गेंदें शामिल होंगी। भगवंत सिंह मान ने अधिकारियों को 31 मार्च, 2026 तक गांवों में 5600 खेल किटें वितरित करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह बहुत गर्व और संतोष की बात है कि विभाग द्वारा एक व्यापक खेल पोर्टल शुरू किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि खेल प्रेमी और खिलाड़ी एक क्लिक पर खिलाड़ियों की रजिस्ट्रेशन, ऑनलाइन ग्रेडेशन, ऑनलाइन डी.बी.टी., खेल आयोजन करवाना, ग्राउंड रिजर्वेशन, ई–सर्टिफिकेट, परिणाम रिकॉर्ड करना, पेंशनध्वजीफा और अन्य सुविधाएं प्राप्त कर सकेंगे। भगवंत सिंह मान ने कहा कि 10,000 युवाओं के लिए प्रदेश के नौ जंगली क्षेत्रों में ट्रैकिंग, एडवेंचर, टीम एक्टिविटी कैंप भी लगाए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि आने वाली जनवरी से पल्लणपुर, सिसवां, मिर्जापुर (मोहाली), टिब्बा टपरिया (रोपड़), नारा (होशियारपुर), और हरिके पत्तन रख (तरनतारन) में कैंप लगाए जाएंगे। उन्होंने यह भी कहा कि 43 करोड़ रुपए की लागत से सेक्टर 42ए में एक नया युवा भवन बनाया जाएगा। भगवंत सिंह मान ने कहा कि इसमें 200 युवाओं के लिए हॉस्टल सुविधाएं, 400 व्यक्तियों की क्षमता वाला ऑडिटोरियम, एक कॉन्फ्रेंस हॉल, सेमिनार रूम और अन्य सुविधाएं उपलब्ध होंगी।

तलाकशुदा महिला का दिनदहाड़े किया मर्डर सगे भाई ने ही धारदार हथियार से काटा गला

रोहतक ०७/०१ (संवाददाता): रोहतक के माता दरवाजा चौक क्षेत्र में एक बहुत की दर्दनाक ऑनर किलिंग की वारदात सामने आई। 35 वर्षीय ब्यूटी पार्लर संचालिका माया की उसके सगे भाई ने तेजधार हथियार से गला काटकर हत्या कर दी। घटना गुरुवार सुबह करीब साढ़े दस बजे उस समय हुई, जब माया अपने पार्लर में मौजूद थी। पुलिस ने आरोपित को हिरासत में ले लिया। जांच में सामने आया है माया की शादी करीब दस वर्ष पहले पंजाब में हुई थी। दंपती की कोई संतान नहीं थी। तीन माह पूर्व माया ने पति से तलाक लिया था। अब माया खोखराकोट क्षेत्र में एक युवक के साथ किराये के मकान में रह रही थी। इसी बात को लेकर उसका भाई जवाला प्रसाद नाराज था व बहन के

चरित्र पर संदेह करता था। पूछताछ में उसने बताया कि बहन किसी युवक संग किराए के मकान में उनसे अलग रहती थी। लोग उसे ताने मारते थे। आरोपित ने पुलिस को कहा वो रोज बेइज्जती नहीं सह सकता था। डीएसपी मुख्यालय रवि खुंडिया ने बताया पुलिस आरोपित को शुक्रवार को अदालत में पेश कर रिमांड पर लेगी। दूसरी युवती डरकर बेहोश वीरवार सुबह माया रोज की तरह अपने ब्यूटी पार्लर पहुंची थी। पार्लर में उसकी एक सहयोगी कर्मी लक्ष्मी भी मौजूद थी। इसी दौरान माया का बड़ा भाई कबीर कालोनी निवासी जवाला प्रसाद वहां पहुंचा और तेजधार हथियार से माया की गर्दन पर वार कर दिया। गंभीर चोट लगने से माया की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं, सहयोगी कर्मी लक्ष्मी सहमकर बेहोश हो गई।

हिमाचल में सामूहिक अवकाश पर 2850 डॉक्टर, डा. की बर्खास्तगी का फैसला वापस नहीं लेने पर हड़ताल की दी चेतावनी

शिमला ०७/०१ (संवाददाता): इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल (आइजीएमसी) शिमला में डॉक्टर व मरीज के बीच मारपीट के मामले के बाद पल्मोनरी विभाग के सीनियर रेजिटेंड डॉ. राघव निरूला की बर्खास्तगी के विरोध में प्रदेश के डॉक्टर संगठन मुखर हो गए हैं। आइजीएमसी रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन (आरडीए), हिमाचल प्रदेश मेडिकल आफिसर एसोसिएशन (एचपीएमओए) और स्टेट एसोसिएशन ऑफ मेडिकल एंड डेंटल कालेज टीचर्स (सेमडिकोट) ने निर्णय बदलने की मांग की है। आरडीए ने चेतावनी दी कि अगर सरकार ने 26 दिसंबर को डॉक्टर की बर्खास्तगी का फैसला वापस नहीं लिया तो 27 दिसंबर से वे प्रदेशभर में हड़ताल पर चले जाएंगे। आरडीए की घोषणा के बाद 26 दिसंबर को आइजीएमसी में 450 डॉक्टर सामूहिक अवकाश पर रहेंगे। हिमाचल प्रदेश मेडिकल आफिसर एसोसिएशन के प्रेस सचिव डॉ. विजय ने जारी बयान में कहा कि शुक्रवार को प्रदेशभर के 2400 डाक्टर सामूहिक अवकाश पर रहेंगे। एसोसिएशन ने भी आरडीए के समर्थन में शुक्रवार को एक दिन के सामूहिक अवकाश पर जाने का फैसला किया है। आरडीए के अध्यक्ष डॉ. सोहेल शर्मा ने चेतावनी दी कि यदि मुख्यमंत्री से बैठक के बाद भी मांगों पर कार्रवाई नहीं हुई तो 27 दिसंबर सुबह 9रू30 बजे से हड़ताल शुरू की जाएगी। इस दौरान ओपीडी, वैकल्पिक ऑपरेशन और नियमित सेवाएं बंद रहेंगी, जबकि आपातकालीन सेवाएं जारी रहेंगी। डॉक्टरों के साथ हो रहे अन्याय को देखते हुए संगठन ने एक दिन की सामूहिक आकस्मिक छुट्टी (सीएल) लेने का निर्णय लिया है। हिमाचल प्रदेश मेडिकल आफिसर एसोसिएशन के प्रेस सचिव डॉ. विजय ने आरडीए के रुख का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि 26 दिसंबर को सुबह आइजीएमसी के रेजिडेंट डॉक्टर मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू से मुलाकात डॉ. राघव को बर्खास्त करने का निर्णय वापस लेने का आग्रह करेंगे। मुलाकात के बाद आरडीए जो भी निर्णय लेगा, एचपीएमओए उसका समर्थन करेगा। सेमडिकोट के अध्यक्ष डॉ. बलवीर वर्मा ने बताया कि मुख्यमंत्री से मिलने के लिए समय मांगा है और मुलाकात के बाद ही आगामी रणनीति तय की जाएगी।

Printed, Published,Edited, & Owned by Prakash Kumar Dhal, Printed at Promodini Publication, Main road , Chhend colony , Rourkela-15 & Published at ECR-73, Chhend Colony, Rourkela-15, Editor : Prakash kumar Dhal, Email:kalingasamachar@gmail.com , Mob: 9439951525, Ph. 0661-2646999

ओडिशा समाचार

कलिंग समाचार

राउरकेला, गुरूवार 08 जनवरी 2026

सुंदरगढ़ के दृष्टिबाधित संगीतकारों ने अपनी प्रतिभा को आजीविका में बदला

राउरकेला ०७/०१ (संवाददाता): घोर गरीबी और शारीरिक सीमाओं के आगे हार न मानते हुए, सुंदरगढ़ जिले के ग्रामीण इलाकों के दृष्टिबाधित संगीत प्रतिभाओं के एक छोटे समूह ने मिलकर संगीत के ज़रिए आत्मनिर्भर जीवन जीने का रास्ता खोज लिया है। मंदिरों, धार्मिक, सामाजिक और अन्य कार्यक्रमों में प्रदर्शन करके, ये संगीत समूह अपना गुज़ारा करते हैं और अपने परिवारों का भी पेट पालते हैं।

इस पहल के पीछे अक्षय कुमार तिवारी (30) हैं, जो खुद भी दृष्टिबाधित हैं और भुवनेश्वर के उत्कल संगीत महाविद्यालय के पूर्व छात्र हैं। राउरकेला शहर के रहने वाले तिवारी अपने परिवार और छोटे ऑर्केस्ट्रा समूह के साथ सुंदरगढ़ के सुबडेगा ज़्लॉक के सुबलाया में बस गए हैं।यह सब जून 2018 में ऑर्केस्ट्रा समूह उत्कल ज्योति दिव्यांग भजन मेलोडी संध्या के गठन के साथ शुरू हुआ। तिवारी बताते हैं कि उन्होंने इंटरमीडिएट पूरा किया और भुवनेश्वर में ओडिसी संगीत की पढ़ाई की। हालांकि, अपनी ट्रेनिंग पूरी करने और भुवनेश्वर से लौटने के बाद, उन्हें पता चला कि वह अकेले नहीं हैं। संगीत का शौक रखने वाले कई दृष्टिबाधित लोग थे, लेकिन उन्हें कोई सहारा या मंच नहीं मिला और उन्हें अपना जीवन चलाने के लिए भीख मांगने पर मजबूर होना पड़ा।लोग आमतौर पर हमें दया की नज़र से देखते थे और कभी-कभी मदद करते थे।

हमारे अपने परिवारों में भी, हमें सीधे या परोक्ष रूप से जीवन भर का बोझ माना जाता था। मैं भी उन्हीं जैसा था, इसलिए मैं उनके दर्द, भावनाओं और लाचारी को आसानी से समझ सकता था, तिवारी कहते हैं। तभी उन्होंने इन अनजान लेकिन संगीत में प्रतिभाशाली शारीरिक रूप से अक्षम लोगों को संगठित करने और एक ऑर्केस्ट्रा बनाने का फैसला किया।शुरुआती दौर संघर्षों से भरा था। हमें कोई मदद नहीं मिली। लोग हमें हमारी अक्षमता के कारण देखते थे, हमारी क्षमता के कारण नहीं। लेकिन हमारा पक्का इरादा था और हम डटे रहे। हमने सड़कों पर प्रदर्शन करना शुरू किया और धीरे-धीरे दर्शक मिलने लगे, तिवारी कहते हैं। हालांकि, जैसे ही उन्होंने शुरुआत की थी, कोविड-19 महामारी के रूप में एक और बड़ी बाधा सामने आ गई। समूह टूट गया ज़्योंकि संगीत प्रदर्शन करना असंभव हो गया और वे जीवित रहने के तरीके खोजने लगे। महामारी के लगभग दो साल बाद, वे फिर से एक साथ आए, लेकिन लोगों तक पहुंचना एक चुनौती थी। तिवारी ने बताया कि समूह के प्रचार के लिए, उन्होंने सड़कों पर शो किए जहां लोगों ने कुछ पैसे दान किए। धीरे-धीरे, कुछ लोग अपने समारोहों, कार्यक्रमों या त्योहारों में संगीत कार्यक्रमों के लिए उनसे संपर्क करने लगे। जो एक छोटी सी शुरुआत थी, वह अब एक छोटी धारा बन गई है। तिवारी कहते हैं, हमारा ग्रुप धीरे-धीरे पॉपुलर हो रहा है। आजकल हमें मंदिर समितियों, धार्मिक और पारिवारिक कार्यक्रमों, जैसे जनेऊ संस्कार, जन्मदिन और सामुदायिक कार्यक्रमों के लिए ज़्यूजिकल परफॉर्मेंस के लिए संपर्क किया जाता है। ग्रुप का पसंदीदा ज़्यूजिकल जॉनर भजन और भक्ति गीत हैं, लेकिन यह ग्रुप फिल्मी धुनों और दूसरे पॉपुलर गानों में भी उतना ही माहिर है। ग्रुप आमतौर पर सात से आठ सदस्यों के साथ परफॉर्म करता है, जो कभी-कभी बढ़कर 10 से 12 हो जाते हैं। तिवारी सिंगर और कीबोर्ड ज़्यूजिशियन दोनों के तौर पर ग्रुप को लीड करते हैं। राजेश बारला (40) गाने और मृदंग बजाने दोनों में माहिर हैं, जबकि कृष्णा माझी (26) इलेज़्ट्रॉनिक ज़्यूजिकल पैड बजाने में माहिर हैं। दूसरों में कर्ण बंदा (42) और सुरेश शामिल हैं। ग्रुप के ज़्यादातर सदस्यों में एक से ज़्यादा टैलेंट हैं। वे आमतौर पर मृदंग, तबला, ढोल और ताशा जैसे छोटे पारंपरिक वाद्ययंत्रों के साथ इलेज़्ट्रॉनिक पैड का इस्तेमाल करते हैं। तिवारी की पत्नी, सुचित्रा करोली, ग्रुप की असल में मुज़्य ऑर्गनाइज़र और मैनेजर हैं। करोली ने बताया कि दृष्टिबाधित ज़्यूजिशियन सुंदरगढ़ के अलग-अलग हिस्सों से आते हैं और उनमें से कुछ का कोई परिवार नहीं है। कुछ हमारे साथ सुबलाया में रहते हैं, जबकि जो अपने परिवारों के साथ रहते हैं, उन्हें परफॉर्मेंस के दौरान बुलाया जाता है। वे अपने ज़्यूजिकल स्किल्स को बेहतर बनाने के लिए रोज़ प्रैज़्टिस करते हैं, वह कहती हैं।उन्हें मिलने वाले मेहनताने के बारे में, वह कहती हैं कि दूरी के हिसाब से, वे दो घंटे की परफॉर्मेंस के लिए ?6,000 से ?15,000 तक चार्ज करते हैं। ग्रुप की पॉपुलैरिटी सुंदरगढ़ से बढ़कर पड़ोसी जिलों तक फैल गई है। शुक्रवार शाम को, बैंड ने झारसुगुड़ा जिले के पंचगाँव में एक यज्ञ कार्यक्रम में परफॉर्म किया।

ग्रुप को आर्थिक रूप से मुश्किल समय में संघर्ष करना पड़ता है, लेकिन वे एक परिवार की तरह जीवन के सुख-दुख को एक साथ बांटते हैं। दिल को छू लेने वाले गाने और धुनों से दर्शकों का मनोरंजन करते हुए, वे ऐसा टैलेंट दिखाते हैं जिसे शारीरिक सीमाओं से रोका नहीं जा सकता। इस ग्रुप ने सदस्यों को अपने ज़्यूजिकल पैशन को जीने और रोज़ी-रोटी कमाने में भी मदद की है, करोली कहती हैं।

माझी ने डॉ. हरेकृष्ण महताब की आदमकद प्रतिमा की घोषणा की

भुवनेश्वर ०७/०१ (संवाददाता): मुज़्यमंत्री मोहन चरण माझी ने उत्कल केशरी डॉ. हरेकृष्ण महताब को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि आज़ादी की लड़ाई और आज़ादी के बाद के समय में ओडिशा में ज़्यादातर बड़े आंदोलन और विरोध या तो उन्होंने ही किए थे या उनके विज़न और लीडरशिप से प्रेरित थे।

डॉ. महताब की 39वीं पुण्यतिथि, जिसे स्वाधीनता संग्रामी महोत्सव के तौर पर मनाया जाता है, के मौके पर यहां स्वाधीनता संग्रामी सदन में आयोजित एक राज्य-स्तरीय कार्यक्रम को संबोधित करते हुए, मुज़्यमंत्री ने इस मौके को हर ओडिया के लिए गर्व का पल बताया। उन्होंने कहा कि डॉ. महताब भारत के सबसे महान स्वतंत्रता सेनानियों में एक खास जगह रखते हैं और उन्होंने मॉडर्न ओडिशा को बनाने में अहम भूमिका निभाई।

बड़ी पहलों की घोषणा करते हुए, माझी ने कहा कि डॉ. महताब की एक आदमकद मूर्ति जल्द ही भुवनेश्वर के एक सेंट्रल लोकेशन पर लगाई जाएगी।

उन्होंने यह भी बताया कि स्वतंत्रता सेनानियों के परिवारों के लिए एक कुटुंब योजना प्रोसेस में है और जल्द ही इसे लागू किया जाएगा। राज्य के महान सपूतों का सज़्मान करना नैतिक ज़िज़्मेदारी बताते हुए, माझी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से प्रेरित होकर उनकी सरकार ने लगातार मशहूर हस्तियों की जयंती और पुण्यतिथि उनके पैतृक गांवों में मनाकर उनकी विरासत को पहचानने और बचाने का काम किया है।

सुंदरगढ़ में गजराज का आतंक, नुकसान

राउरकेला ०७/०१ (संवाददाता): सुंदरगढ़ जिले के लाठीकटा तथा सबडेगा ज़्लॉक में 81 हाथियों के झुंड ने आतंक मचा रखा है। हाथियों के द्वारा फ्सल को नुकसान पहुंचाने से किसानों की नींद हराम हो गई है। वन विभाग की ओर से इन्हें खदेड़ने का प्रयास किया जा रहा हैए लेकिन सफ्लता नहीं मिल रही है। लाठीकटा ज़्लॉक में 41 हाथियों के होने से बुचा हांडाए डाइटोलाए रेलापोषए बिरुआल क्षेत्र के लोग हाथियों से आतंकित हैं।सबडेगा ज़्लॉक में 40 हाथियों का झुंड है। वन विभाग की ओर से हाथियों पर नजर रखने के साथ ही गांवों की ओर उन्हें आने से रोकने का प्रयास किया जा रहा है। लाठीकटा ज़्लॉक के बीरकेरा पंचायत क्षेत्र में तीन दिन से 41 हाथियों के झुंड देखा जा रहा है। इनके झारखंड के पश्चिम सिंहभूम जिले के जंगल से इस ओर आने का अनुमान लगाया जा रहा है।इस क्षेत्र में पहले से 21 हाथी थे एवं 20 हाथी और इस झुंड में शामिल हो गए।

स्कूल और कॉलेज राष्ट्रीय युवा दिवस पर 'वंदे मातरम' गाएंगे

भुवनेश्वर ०७/०१ (संवाददाता):एक ऑफिशियल बयान के मुताबिक, ओडिशा के सभी एजुकेशनल इंस्टिट्यूशन 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जयंती और नेशनल यूथ डे के मौके पर पूरे राज्य में वंदे मातरम गाने का प्रोग्राम मनाएंगे। इस मौके पर, स्टूडेंट्स आत्मनिर्भर भारत स्वदेशी संकल्प भी बोलेंगे और हर इंस्टिट्यूशन एक स्टूडेंट को आत्मनिर्भर भारत एंबेसडर के तौर पर नॉमिनेट भी करेगा। स्टूडेंट्स के लिए अलग-अलग कॉज़्पिटिशन ऑर्गनाइज़ किए जाएंगे और अच्छे पार्टिसिपेंट्स को सज़्मानित किया जाएगा। ओडिया लैंग्वेज, लिटरेचर और कल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से जारी एक बयान के मुताबिक, राज्य भर के यूथ ज़्लब भी इस ग्रुप में हिस्सा लेंगे।

डिपार्टमेंट ने सभी डिस्ट्रिज़्ट कलेज़्टर से प्रोग्राम को आसानी से लागू करने के लिए कहा है। गाने को आसानी से करने के लिए, पूरे राज्य में वंदे मातरम ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गनाइज़ किया जा रहा है। जोनल लेवल के ट्रेनिंग प्रोग्राम करने के लिए राज्य को पांच जोन—जयपुर, बरहामपुर, बालासोर, संबलपुर और भुवनेश्वर—में बांटा गया है। दिसंबर में बरहमपुर, बालासोर और जयपुर में जोनल ट्रेनिंग प्रोग्राम हुए, जबकि संबलपुर जोनल ट्रेनिंग 2 जनवरी को पूरी हुई। एक अधिकारी ने बताया कि भुवनेश्वर जोनल ट्रेनिंग शनिवार को खत्म हुई। आज उत्कल यूनिवर्सिटी में हुए भुवनेश्वर जोनल-लेवल ट्रेनिंग प्रोग्राम को संबोधित करते हुए, कल्चर मिनिस्टर सूर्यबंशी सूरज ने कहा कि वंदे मातरम भारत के आज़ादी के आंदोलन की आवाज़ बन गया और आज भी देश की सोच और देशभक्ति की भावना को बढ़ावा देता है। उन्होंने कहा कि यह गाना लोगों में हिज़्मत और ताकत भरता है।

धान खरीद में देरी से ओडिशा के कोरापुट के किसान परेशान

जयपुर ०७/०१ (संवाददाता): धान खरीद के लिए बिक्री टोकन जारी करने में देरी से कोरापुट जिले के किसान परेशान हैं, अब तक सिर्फ़ 40 प्रतिशत रजिस्टर्ड किसानों को ही टोकन मिले हैं। धान खरीद प्रक्रिया 11 दिसंबर को बोरिगुज़्मा ऋस्ष्ट मंडी में शुरू हुई थी। फिलहाल, जयपुर और कोरापुट सब-डिवीजन में लगभग 80 मंडियां पूरी तरह से काम कर रही हैं। जिले के कुल 44,107 किसानों ने इस साल अपनी खरीफ धान बेचने के लिए 20 बड़े एरिया मल्टी-पर्पस कोऑपरेटिव सोसाइटी के ज़रिए रजिस्ट्रेशन कराया है। हालांकि, ज़्यादातर किसानों को अभी तक टोकन नहीं मिले हैं और वे उन्हें पाने के लिए इधर-उधर भटक रहे हैं। नतीजतन, किसानों को अपनी कटी हुई धान की फसल की दिन-रात पहरेदारी करनी पड़ रही है, और ठंड में ठिठुरते हुए फसल बेचने का इंतज़ार करना पड़ रहा है।

कोरापुट कृषक कल्याण मंच के नेता नरेंद्र प्रधान ने कहा, अधिकारियों को टोकन जारी करने की प्रक्रिया की तुरंत समीक्षा करनी चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि रबी की खेती का मौसम शुरू होने से पहले सभी रजिस्टर्ड किसानों को टोकन मिल जाएं। इसके अलावा, कथित तौर पर सिविल सप्लाई और उपभोक्ता कल्याण विभाग या कोऑपरेटिव सोसाइटी के डिप्टी रजिस्ट्रार के ऑफिस में, जो दोनों धान खरीद की देखरेख करते हैं, जिला स्तर पर टोकन ट्रैक करने या जारी करने का कोई सिस्टम नहीं है। डिप्टी रजिस्ट्रार के ऑफिस के एक सीनियर अधिकारी ने कहा, हम किसानों के टोकन की स्थिति को ट्रैक करने में लाचार हैं, ज़्योंकि पूरी प्रक्रिया राज्य स्तर पर संभाली जाती है। जिला स्तर पर टोकन जारी करने का कोई प्रावधान नहीं है। हमारी भूमिका सिर्फ़ यह सुनिश्चित करना है कि किसानों को टोकन मिलने के बाद मंडियों में खरीद सुचारू रूप से हो।

आरएसपी द्वारा आयोजित सिलाई प्रशिक्षण के पहले चरण को बंडामुंडा ग्राम पंचायत की 15 महिलाओं ने सफलतापूर्वक पूरा किया

राउरकेला ०७/०१ (संवाददाता): राउरकेला इस्पात सयंत्र द्वारा आयोजित बंडामुंडा ग्राम पंचायत की पंद्रह महिलाओं को, परिधीय विकास संस्थान में 15-दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में उद्योग ग्रेड सिलाई मशीनों के सिलाई और संचालन में पहले चरण में प्रशिक्षित किया गया था। कार्यक्रम का समापन समारोह 23 दिसंबर 2025 को आयोजित किया गया था। कार्यक्रम का उद्देश्य वंचित महिलाओं के कौशल को विकसित करना और बंडामुंडा में एक प्रशिक्षण सह उत्पादन केंद्र (टीसीपीसी) स्थापित करना है। प्रत्येक प्रशिक्षु को एक वाणिज्यिक ग्रेड सिलाई मशीन भी प्रदान की जाएगी। सिलाई सत्र मास्टर ट्रेनर (उषा सिलाई स्कूल) सुश्री मोनालीशा साहू द्वारा आयोजित

किए गए थे। मुज़्य महाप्रबंधक (नगर सेवाएं एवं सीएसआर), श्री टी. जी. कानेकर समापन समारोह के मुज़्य अतिथि थे और उन्होंने सभी प्रशिक्षुओं को पूरा होने का प्रमाण पत्र सौंपा। इस अवसर पर महाप्रबंधक प्रभारी (सीएसआर), सुश्री मुनमुन मित्रा, उप महाप्रबंधक (सीएसआर),श्री टीबी टोप्पो,उप प्रबंधक (सीएस आर), श्री एस के सुकुला, परियोजना प्रबंधक, ग्राम उत्थान, श्री गुरु प्रसाद मोहंती, एवं आरएसपी और संबंधित एजेंसियों के अन्य अधिकारी उपस्थित थे। इस अवसर पर श्री कानेकर ने परिधीय गांवों की महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में किए गए सीएसआर प्रयासों की सराहना की। उन्होंने सभी से अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए अवसर का सर्वोज़ाम उपयोग करने का आग्रह किया। प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षुओं द्वारा बनाए गए सर्वश्रेष्ठ उत्पाद जैसे पुरुषों, महिलाओं, बच्चों के साथ-साथ रसोई एप्रन, कढ़ाई और पिपली कार्य आदि के लिए कपड़े भी इस अवसर पर प्रदर्शित किए गए थे। 15 दिनों के प्रशिक्षण के पहले चरण के तहत, महिलाओं को सिलाई मशीनों की स्थापना, मरज़्मत और सर्विसिंग, डिजाइनिंग और पैटर्न तैयार करना, माप तकनीक और काटने, सिलाई और सिलाई, परिधान फ़िटिंग, हेमिंग और इंटरलॉकिंग, पैकेटिंग और उपवास और अन्य विशिष्ट परिधान सिलाई प्रशिक्षण सिखाया गया था। पहले चरण के पूरा होने के बाद, बंडामुंडा में एक प्रशिक्षण सह उत्पादन केंद्र (टीसीपीसी) स्थापित किया जाएगा, जिसमें सामान्य और वाणिज्यिक दोनों श्रेणियों की सिलाई मशीन और एक बहु-कार्यात्मक सिलाई मशीन होगी। दूसरा चरण छह महीने की अवधि के बाद 10 दिनों का रिफ्रेशर ऑनसाइट प्रशिक्षण पाठ्यक्रम होगा। तीसरे चरण में प्रशिक्षुओं को मूल्यवर्धन की दिशा में एक उपाय के रूप में कटवर्क पिपली प्रशिक्षण में 10 दिनों के विशेष प्रशिक्षण के साथ प्रदान किया जाएगा। पूर्ण प्रशिक्षण के बाद प्रशिक्षित महिलाओं को एक निर्माता समूह के रूप में पंजीकृत किया जाएगा और बड़े आदेशों के लिए ओआरएमएएस के साथ संबंध स्थापित किया जाएगा। बंडामुंडा ग्राम पंचायत में प्रशिक्षण सह उत्पादन केंद्र (टीसीपीसी) के प्रशिक्षण और स्थापना की कुल लागत रुपये होगी। 11.98 लाख रुपये शामिल हैं। व्यावसायिक व्यवसाय गतिविधि शुरू करने के लिए सीड राशि के रूप में 35,000.00 रूपये दिए गए 7

शुरुआत में सुश्री मित्रा ने उद्घाटन भाषण दिया। श्री एस के सुकुला ने औपचारिक धन्यवाद ज्ञापित किया, जबकि अनुभाग सहयोगी (सीएस आर), एमडी ज़ाहिद अख़्तर ने समारोह का समन्वय किया।